साप्ताहिक
शहर सत्ता
RNI TITLE CODE - CHHHIN17596
सोमवार, 18 अगस्त से 24 अगस्त 2025
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 04 में...
मकानों से ऊँची सड़कें...

पेज 06 में...
राहुल को चुनाव आयोग की दो टूक

वर्ष : 01 अंक : 24 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 09 सीएम के निर्देश पर डिजिटल क्रॉप सर्वे

पुलिस आयुक्त... कितने उपयुक्त ?

- जिलाबदर और निषेधाज्ञा का मिलेगा संपूर्ण अधिकार
- पदनाम, प्रशासनिक शक्तियोन में टकराव की संभावना
- एडीजी, आईजी और डीआईजी रैंक को मिलेगी पोस्टिंग
- पुलिस कमिश्नर मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से रखेंगे राफ्ता
- एसपी और एएसपी स्तर के अफसर करेंगे सिर्फ बाबूगिरी
- सिर्फ जनसंख्या नहीं अपराध का स्तर से भी प्रणाली तय
- रमन और भूपेश सरकार में थी लागू होने की सुगबुगाहट
- सेंट्रल क्राइम ब्रांच के लिए रमन सरकार ने की थी कवायद

सिस्टम लागू होने पर महकमे में छिड़ेगी वर्चस्व की लड़ाई

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

20 लाख से ज्यादा आबादी वाली राजधानी रायपुर की एसएसपी सिस्टम वाली पुलिसिंग अब चरमरा रही है। छत्तीसगढ़ शासन को उम्मीद है कि पुलिस आयुक्त प्रणाली से रायपुर में पुलिसिंग की तस्वीर बदलेगी। कुछ हद तक इसके लाभ भी हैं। सिस्टम लागू हुआ, तो राजधानी में फोर्स भी बढ़ेगी और तेजतर्राट अफसर भी। हालांकि मेट्रो सिटी और 20 लाख से ज्यादा आबादी पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने उपयुक्त नहीं मानी जा सकती। जरायम यानि कि जिले में अपराध का स्तर भी दिल्ली-मुंबई की तर्ज पर होना चाहिए। सिर्फ चाकूबाजी, गांजा, यदाकदा नक्सल हरकतों या आतंकी स्लीपर सेल की सक्रियता के मद्देनजर आनन-फानन में पुलिस आयुक्त प्रणाली का एलान करने से पोस्ट, पॉवर और सिनियरटी के लिए लाभ-हानि दोनों तय करना होगा। हालांकि, रमन सरकार के आखिरी टाईम में भी इसकी बात चली थी। फिर सेंट्रल क्राइम ब्रांच के लिए कवायद शुरू हुई और फाइल ठन्डे बास्ते में चली गई। पिछली कांग्रेस सरकार में भी सुगबुगाहट हुई थी, मगर कुछ हुआ नहीं। कड़वा सत्य है कि जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप रहेगा, पुलिस आयुक्त प्रणाली भी उतनी उपयुक्त नहीं हो पायेगी।

शहर सत्ता/रायपुर। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में पुलिस आयुक्त (सीपी) प्रणाली लागू करने का ऐलान किया। यह फैसला लंबे मंथन और अध्ययन के बाद लिया गया है। माना जा रहा है कि राजधानी की बढ़ती आबादी और लगातार बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए इस प्रणाली से बेहतर कोई विकल्प नहीं बचा है। घोषणा हो गई, केबिनेट के बाद सदन में मंजूरी और फिर नियमों-शक्तियों के लिए लंबी प्रक्रिया में यह प्रयोग उलझकर नहीं रह जाये।

पिछले करीब डेढ़ साल से छत्तीसगढ़ में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लेकर मंथन चल रहा है। उप्र, मप्र समेत कई राज्यों में हाल में लागू हुए इस सिस्टम का गृह विभाग ने अध्ययन भी करवाया। रायपुर के अलावा दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली को लाने का प्रस्ताव है। शुरुआत रायपुर से हो रही है। बता दें कि बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे गिने-चुने राज्य बचे हैं, जहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू नहीं हुआ है। पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश और ओड़िसा तक में इसकी शुरूआत हो चुकी है। यूपी, पश्चिम बंगाल में पहले से लागू है और साउथ के स्टेट में तो 20 साल से ज्यादा हो गया।

फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में पेड और रिचार्ज पोस्टिंगों ने पुलिस का कबाड़ा किया और इस सरकार में पेड के साथ भाई साहब वाली पोस्टिंगें इसे खराब कर रही है। कई जिलों में ऐसा हो रहा कि सिफारिशी अफसर एसपी आईजी की सुनना पसंद नहीं कर रहे। पुलिस के इस रिफार्म को सफल बनाने के लिए सिस्टम को कठोर फैसला लेना होगा।

कौन होगा फर्स्ट कमिश्नर?

रायपुर में किस स्तर के अफसर को कमिश्नर बनाया जाएगा, सरकार के तरफ से अभी कोई संकेत नहीं है। मगर यह तय है कि यहां आईजी या एडीजी लेवल का ही कोई कमिश्नर होगा। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में डीजी लेवल के आईपीएस अधिकारी पुलिस कमिश्नर होते हैं। एडीजी में प्रदीप गुप्ता, विवेकानंद, अमित कुमार और दीपांशु काबरा। आईजी अमरेश मिश्रा, डीआईजी आजातशत्रु बहादुर सिंह के नाम आयुक्त प्रणाली के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं।

बढ़ते अपराध पर अंकुश की उम्मीद

राजधानी समेत प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती, चोरी और दुष्कर्म जैसे अपराध लगातार बढ़ रहे थे। गंभीर घटनाओं के दौरान पुलिस की धीमी प्रतिक्रिया से सरकार की छवि पर भी सवाल उठते रहे। नए सिस्टम से पुलिस न केवल तेजी से प्रतिक्रिया दे सकेगी बल्कि जवाबदेही भी तय होगी। पुलिस को मिल जाएंगे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के अधिकार, तुरंत कार्रवाई होगी।

सिर्फ घोषणा से कुछ नहीं होता

प्रदेश सरकार द्वारा कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की घोषणा पर भूपेश बघेल ने कहा कि सिर्फ घोषणा करने से कुछ नहीं होता। भाजपा जो कहती है, वह करती नहीं है। प्रदेश में बिजली बिल के नाम पर लूट मची हुई है। लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। गृहमंत्री विजय शर्मा के क्षेत्र कवर्धा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ग्राउंड में मारपीट का मामला सामने आया है। जिसने मारपीट की उसको निमंत्रण देकर बुलाया गया था।

साप्ताहिक शहर सत्ता

इसलिए जरूरी है रायपुर में नया सिस्टम

राजधानी रायपुर की आबादी 20 लाख पार कर चुकी है। मौजूदा एसएसपी प्रणाली में 33 थानों का जिम्मा सिर्फ एक अधिकारी के पास होता है। नतीजा, किसी बड़ी घटना पर ध्यान केंद्रित होते ही बाकी इलाके निगरानी से छूट जाते हैं। वीवीआई मूवमेंट के अलावा कानून व्यवस्था से जुड़े मामले लगभग रोज आते हैं। इसमें अपराधों की लगातार निगरानी, खुफिया तंत्र मजबूत करने से लेकर बुनियादी पुलिसिंग के सारे काम बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। पुलिस आयुक्त सिस्टम में एडीजी या वरिष्ठ आईजी स्तर का अधिकारी पुलिस आयुक्त होगा। शहर को छह से आठ जोन में बांटा जाएगा। हर जोन की कमान एसपी स्तर के पुलिस उपायुक्त के पास होगी और उनके अधीन दो-तीन एसीपी (एडिशनल एसपी-डीएसपी) होंगे। हर एसीपी सिर्फ 2-3 थानों की जिम्मेदारी देखेगा। इससे निगरानी और त्वरित कार्रवाई में आसानी होगी। यानि जिस शहर को एक एसपी संभाल रहा है, वहां पर छह से आठ एसपी होंगे।

सीपी सिस्टम के प्रमुख फायदे

- तेज और स्पष्ट निर्णय क्षमता पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुमति का इंतजार नहीं।
- जिम्मेदारी सुनिश्चित - किसी गड़बड़ी पर जवाबदेही तय होगी।
- शहरी चुनौतियों के अनुकूल भीड़, अपराध, ट्रैफिक और आंदोलनों से निपटना आसान।
- एकीकृत कमान - पुलिस और प्रशासन की दोहरी जिम्मेदारी से छुटकारा, सीधे पुलिस नियंत्रण।

68 से ज्यादा शहरों में लागू

भारत में पुलिस आयुक्त प्रणाली का तेजी से विस्तार हो रहा है। बीपीआरडी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 तक 15 राज्यों के 61 शहरों में यह प्रणाली थी, अब यह संख्या 68 से ज्यादा हो चुकी है। दिल्ली, चुका है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ और जयपुर जैसे महानगर पहले से ही इस व्यवस्था में हैं। महाराष्ट्र सबसे आगे है, जबकि छत्तीसगढ़ अब इस सूची में कदम रखने जा रहा है।

यहां लागू है कमिश्नरी व्यवस्था

छत्तीसगढ़ सरकार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लागू कमिश्नर प्रणाली को अपना सकती है। यहां कमिश्नर को सीमित मजिस्ट्रीयल पॉवर्स ही हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में कमिश्नरी की व्यवस्था है। वहां छोटे मामलों में वो मजिस्ट्रेट के अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन लाइसेंसिंग वगैरह का जिम्मा डीएम के हाथों में ही है। जबकि पंजाब, दिल्ली और मुंबई में लाइसेंस वगैरह जारी करने के अधिकार भी कमिश्नर के पास होता है। फिलहाल उत्तरप्रदेश के लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, कानपुर और नोएडा यानी गौतमबुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था है।

पुलिस आयुक्त पद से गड़बड़ाएगा तालमेल

कमिश्नरी बन जाने से सबसे बड़ा फर्क ये पड़ता है कि जिला पुलिस का मुखिया एक अनुभवी और ऊंचे रैंक वाला अफसर बन जाता है। विभाग में बहुत सारे निर्णय पुलिस स्तर पर होने लगतेह। जरुरत के मुताबिक पुलिस फोर्स मिलने में दिक्कत नहीं आती। फौजदारी मामलों की सुनवाई एसडीएम लेबल के अफसरों को करने होते हैं, वो पुलिस कमिश्नर के पास आ जाते हैं। हालांकि राज्य सरकार चाहे तो इसे रोक भी सकती है, लेकिन उस स्थिति में कमिश्नरी बनाने का औचित्य खत्म हो जाएगा। बहुत से छोटे मसले ऐसे होते हैं, जिनमें पुलिस और एसडीएम के बीच तालमेल की कमी से बात बिगड़ जाती है। जबकि एसीपी या डीसीपी स्तर के अफसर के पास ये अधिकार आ जाने से पुलिस के काम काज में सुविधा होती है। जैसे किसी को पाबंद करना या निषेधाज्ञा वगैरह लागू करना। दीवानी वाले मामले एसडीएम के पास ही रहते हैं।

जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका

छत्तीसगढ़ जैसे जनजाति बहुल राज्य में डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट की भूमिका पर कोई खास असर पड़ने की संभावना बहुत कम है। क्योंकि राजस्व के काम इस कदर उलझे रहते हैं कि उसके अधिकारों में कटौती से काम काज प्रभावित नहीं होगा। इस लिहाज से एसडीएम और डीएम अपने पूरे अधिकारों के साथ रहेंगे। लेकिन रैली, प्रदर्शनों में बल प्रयोग या अनुमति का अधिकार छिन सकता है।

बदल जायेंगे अफसरों के पदनाम

कमिश्नर अपने अधिकार अपने मातहत अफसरों को देता है। उनके नाम भी उसी के अनुरुप हो जाते हैं। जैसे कमिश्नर के नीचे एडिश्नल कमिश्नर हो सकते हैं। ये राज्य सरकार पर निर्भर करेगा। कमिश्नर की मदद के लिए उसी रैंक के किसी अफसर को एडिश्नल कमिश्नर तैनात करेगे। कमिश्नर अगर आईजी लेबल का बनता है, तो इसके मातहत डीआईजी लेबल के अफसरों को डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए जा सकते हैं। कमिश्नर एडीजी होने की स्थिति में भी डीसीपी ओहदे पर ज्यादातर डीआईजी लेबल के अफसर ही तैनात किए जाएंगे। उनके नीचे एडिशन डीसीपी भी हो सकते हैं, जो एसएसपी और एसपी रैंक के अफसर होते हैं।

क्राइम के आंकड़े

कुल दर्ज अपराध
2023 – 16,125
2024 – 17,193
लगभग 1,068 मामले अधिक

2025 (जनवरी–अगस्त)
7,000+ मामले (अभी साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन औसतन हर महीने ~875 केस, यानी साल के अंत तक यह संख्या 10,000–11,000 तक पहुँच सकती है।)

गंभीर अपराध
2021 – 2,471
2022 – 2,884
2023 – 2,963 (सबसे अधिक)
2024 – 2,608 (कमी दिखी, लेकिन कुल अपराध फिर भी बढ़े)

कुल अपराध लगातार बढ़ रहे हैं – 2023 की तुलना में 2024 में वृद्धि साफ दिखती है।
गंभीर अपराधों में उतार-चढ़ाव – 2023 में उच्चतम स्तर (2963) पर पहुँचने के बाद 2024 में गिरावट (2608) दिखी।
2025 की रफ्तार खतरनाक – 8 महीने में ही 7 हजार केस दर्ज होना बताता है कि अपराध नियंत्रण की स्थिति कमजोर है।
संभावना – यदि यही ट्रेंड रहा तो 2025 के अंत तक कुल केस 2023 और 2024 से ज्यादा हो सकते हैं।

सूदखोर तोमर बंधुओं की संपत्ति होगी कुर्क

रायपुर। राजधानी रायपुर के कुख्यात सूदखोर एवं हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोर्ट ने पुलिस की याचिका स्वीकार करते हुए उनकी संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया है। इसके लिए रायपुर कलेक्टर को चार संपत्तियों की कुर्की संबंधी प्रतिवेदन भेजा गया है।

फरार चल रहे हैं आरोपी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों आरोपी भाई पिछले दो महीने से फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में उद्घोषणा (Proclamation) की कार्यवाही शुरू की। उद्घोषणा की अंतिम तारीख कल तय की गई है। यदि निर्धारित तिथि तक आरोपी अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी।

तलाशी में मिले थे अवैध हथियार

जांच के दौरान आरोपियों के घर की तलाशी ली गई थी, जिसमें पुलिस को अवैध हथियार भी मिले थे। आरोप है कि तोमर बंधु ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देकर, पीड़ितों से जबरन वसूली करते थे। उनके खिलाफ सूदखोरी और अन्य गंभीर प्रकरण भी दर्ज हैं।

गंभीर धाराओं में इनाम घोषित

पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने कुख्यात अपराधी वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 308(2), 111(1) तथा छत्तीसगढ़ ऋणियों संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपी 5 जून 2025 को अपराध करने के बाद से फरार हैं। पुलिस ने उनकी तलाश की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि फरारी के दौरान दोनों आरोपी गंभीर अपराध कर सकते हैं। ऐसे में उनका खुले में घूमना समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। इसी आधार पर रेगुलेशन के पैरा 80-A के तहत कार्रवाई करते हुए इनकी गिरफ्तारी में मदद करने वालों के लिए इनाम घोषित किया गया है।

अंडा ठेला से करोड़पति : तोमर बंधुओं की आपराधिक कमाई की कहानी

रायपुर। 2008 में समता कॉलोनी में अंडे का ठेला लगाने से शुरुआत करने वाला वीरेंद्र तोमर देखते-देखते करोड़पति अपराधी बन गया। शुरू में उसने ब्याज पर छोटी रकम लोगों को दी। धीरे-धीरे सूदखोरी को धंधा बना लिया और 10 से 15 प्रतिशत ब्याज वसूलने लगा। बकाया वसूली के लिए मारपीट, अपहरण और धमकी उसका हथियार बन गए। देखते ही देखते भाठागांव में करोड़ों की हवेली, बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी गाड़ियां और भारी मात्रा में नकदी व सोने का मालिक बन बैठा। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही और रसूखदारों की मेहरबानी ने उसके आपराधिक नेटवर्क को मजबूत किया।

करोड़ों की संपत्ति और अवैध हथियार बरामद

पुलिस ने तोमर बंधुओं के ठिकानों पर छापामारी कर भारी मात्रा में संपत्ति और हथियार जब्त किए हैं। जब्ती सूची इस प्रकार है:

नकद राशि : ₹35,10,300
सोने के आभूषण : 734 ग्राम
चांदी के आभूषण : 125 ग्राम
लक्जरी वाहन : बीएमडब्ल्यू, थार, ब्रेजा
इलेक्ट्रॉनिक सामान : लैपटॉप, आईपैड, सीपीयू, डीवीआर, चेकबुक, एटीएम कार्ड, नोट गिनने की मशीन
दस्तावेज : जमीन की रजिस्ट्री, ई-स्टांप, लेन-देन का रजिस्टर
अवैध हथियार : एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल, पांच तलवारें, जिंदा और आवाजी कारतूस

कांकेर के मलाजकुडूम वाटरफॉल से गिरकर रायपुर के युवक की मौत

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में शनिवार को पिकनिक मनाने आए एक युवक की मलाजकुडूम वाटरफॉल से गिरकर मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब युवक अपने दोस्तों के साथ नहा रहा था। रविवार सुबह पुलिस और नगर सेना की टीम ने शव को बरामद किया। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है।

पैर फिसलने से हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, रायपुर निवासी गोपाल चंद्राकर अपने पांच दोस्तों के साथ शनिवार को मलाजकुडूम वाटरफॉल पहुंचा था। नहाने के दौरान वह चिकने पत्थर पर फिसल गया और गहरी खाई में गिर पड़ा। साथियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।

अंधेरे के कारण रात में नहीं हो सका रेस्क्यू

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और नगर सेना की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन अंधेरा होने की वजह से शनिवार देर रात तक रेस्क्यू अभियान नहीं चल पाया। रविवार सुबह टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और गोपाल का शव पानी से बरामद किया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

शराब के नशे में हंगामा करने वाला टीचर गिरफ्तार

डॉक्टर-स्वीपर का गला दबाया, नर्स से गाली-गलौज

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में शराब के नशे में धुत एक शिक्षक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) शंकरगढ़ में जमकर उत्पात मचाया। उसने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और स्वीपर का गला दबाया, नर्स से गाली-गलौज की और अस्पताल में तोड़फोड़ की। स्थिति बिगड़ने पर अस्पताल स्टाफ और मौजूद लोगों ने आरोपी के हाथ-पैर बांध दिए और फर्श पर लिटाकर काबू किया। आरोपी शिक्षक का नाम प्रबोध एक्का (40 वर्ष) है, जो जशपुर जिले के सोनक्यारी का निवासी और शंकरगढ़ ब्लॉक के रेहड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल में लैब अटेंडेंट (एलबी) के पद पर पदस्थ है। 15 अगस्त की रात उसने शराब पीकर पहले घर के आसपास उत्पात मचाया। इसके बाद साथी उसे इलाज के लिए शंकरगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल पहुंचते ही प्रबोध ने ड्यूटी डॉक्टर आफताब अंसारी, स्वीपर सुरेश काशी और स्टाफ नर्स तारा एक्का के साथ गाली-गलौज की। बीच-बचाव करने गए डॉक्टर का गला दबा दिया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया।

ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर दौड़ा

घटना की सूचना मिलते ही शंकरगढ़ थाने से तीन पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। इसी बीच आरोपी ने ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया और पुलिसकर्मियों व स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने के लिए दौड़ा। हालात बिगड़ते देख लोग वहां से भागे। बाद में स्टाफ और ग्रामीणों ने मिलकर उसे काबू किया और हाथ-पैर बांधकर अस्पताल में ही रख दिया।

15 साल की नाबालिग से रेप, 61 साल का संदिग्ध गिरफ्तार

रायपुर। रायपुर में 15 साल की नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। नाबालिग ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक 61 साल के व्यक्ति को हिरासत में लिया है। यह पीड़िता के पड़ोस में ही रहता है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि DNA जांच और पीड़िता के बयान के बाद स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। यह पूरा मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। पुरानी बस्ती थाना प्रभारी योगेश कश्यप ने बताया कि बच्चे का जन्म 23 जुलाई को हुआ है। पीड़िता 15 साल की नाबालिग है। परिवार के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। जिसमें एक 61 साल के व्यक्ति पर रेप का आरोप है। संदिग्ध पीड़िता के पड़ोस में ही रहता है, वह नगर निगम में संविदा कर्मचारी है। हालांकि] पुलिस का कहना है कि इस मामले में DNA रिपोर्ट के बाद स्थिति और साफ हो पाएगी। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि घटना करीब साल भर पहले की है। पीड़िता का परिवार रोजी मजदूरी करता है।

एक्स-गर्लफ्रेंड के पति को मारने भेजा पार्सल बम

होम थिएटर स्पीकर में फिट किया गया 2 किलो बारूद, 7 आरोपी गिरफ्तार

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में एक्स-गर्लफ्रेंड के पति की हत्या की नीयत से एक युवक ने पार्सल बम तैयार कर भेजा। बम को होम थिएटर स्पीकर में फिट किया गया था। पार्सल मिलते ही संदेह होने पर जब उसे खोला गया तो अंदर जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर बरामद हुए। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए शनिवार को मास्टरमाइंड विनय वर्मा सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गंडई थाना क्षेत्र का है। 16 अगस्त को मानपुर निवासी अफसार खान के घर एक पार्सल पहुंचा। बाहर से यह बिल्कुल नया होम थिएटर लग रहा था, लेकिन उसे उठाते ही अफसार को शक हुआ। स्पीकर असामान्य रूप से भारी था और पावर पिन टूटा हुआ दिख रहा था। सावधानी बरतते हुए जब स्पीकर खोला गया तो अंदर तारों से जुड़ा डेटोनेटर और जिलेटिन की छड़ें पाई गईं। अफसार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को सील कर दिया और विस्फोटक को निष्क्रिय किया।

करंट से सक्रिय होता था बम

जांच में सामने आया कि स्पीकर को बिजली से जोड़ते ही करंट डेटोनेटर तक पहुंचता और जोरदार धमाका होता। स्पीकर टुकड़ों में बिखरकर घातक छर्रों में बदल जाता। पुलिस ने शक के आधार पर आईटीआई स्टूडेंट विनय वर्मा को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया और बताया कि योजना में उसके अलावा छह और लोग शामिल थे।

अवैध बारूद खदानों से लाया गया

पुलिस के अनुसार, योजना में शामिल परमेश्वर वर्मा, गोपाल वर्मा, घासीराम वर्मा, दिलीप धिमर, गोपाल खेलवार और खिलेश वर्मा की भी भूमिका सामने आई है। परमेश्वर वर्मा ने जिलेटिन खरीदने के लिए 6 हजार रुपए दिए। गोपाल वर्मा ने पार्सल डिलीवरी में मदद की। खिलेश वर्मा ने इंडिया पोस्ट का फर्जी लोगो और एड्रेस तैयार किया। घासीराम वर्मा ने सप्लायरों से संपर्क किया। दिलीप धिमर और गोपाल सतनामी ने जिलेटिन उपलब्ध कराया।

साप्ताहिक शहर सत्ता

रायपुर में मकानों से ऊंची सड़क घरों में इसलिए घुस रहा पानी

नवीनीकरण में मिलिंग प्रक्रिया को नजरअंदाज करने से बढ़ी समस्या

रायपुर। शहर की कई कॉलोनियों और इलाकों में बरसात के दिनों में लोगों को घरों में पानी घुसने की परेशानी झेलनी पड़ रही है। कारण यह है कि बार-बार सड़क मरम्मत के दौरान बिना पुरानी सतह हटाए डामर की नई परतें बिछाई जाती रहीं। इससे सड़कें आसपास के मकानों से ऊंची हो गई हैं। जिन मकानों की प्लिंथ (नींव) पहले सड़क से ऊपर थी, अब वे नीचे चली गई हैं। नतीजा यह है कि थोड़ी सी बारिश होते ही गंदा पानी सीधे घरों में घुस रहा है। शंकर नगर चौक से बिलासा ब्लड बैंक तक बनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सड़कें इसका प्रमुख उदाहरण हैं। यहां कभी मकान सड़क से 2 फीट ऊंचे थे, लेकिन लगातार डामरीकरण के कारण अब वही मकान सड़क से 2 फीट नीचे हो गए हैं। कुल मिलाकर सड़क की ऊंचाई 4 फीट तक बढ़ गई है। विशेषज्ञों के अनुसार सड़क के नवीनीकरण से पहले पुरानी सतह को मशीन से खुरच कर हटाना जरूरी होता है। इस प्रक्रिया को मिलिंग कहा जाता है। लेकिन रायपुर में यह प्रक्रिया अपनाने के बजाय सीधे नई परत बिछा दी गई। पहले नगर निगम और अब लोक निर्माण विभाग दोनों ही जिम्मेदार विभागों ने इस गलती को दोहराया है।

प्रमुख अभियंता ने माना समस्या

रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने 21 जनवरी को इस मामले को लेकर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता से मुलाकात की थी। अगले ही दिन यानी 22 जनवरी को प्रमुख अभियंता ने रायपुर के मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर माना कि शंकर नगर से लोधीपारा तक लगातार डामरीकरण से सड़क की ऊंचाई काफी बढ़ गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि भविष्य में सड़क निर्माण तभी किया जाए जब पहले मिलिंग प्रक्रिया अपनाई जाए।

नगर निगम पर भी हो लागू

नितिन सिंघवी ने 3 फरवरी को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आग्रह किया कि मिलिंग की यह व्यवस्था सिर्फ PWD तक सीमित न रहे, बल्कि नगर निगम और अन्य नगरीय निकायों पर भी लागू हो। उनका कहना है कि रायपुर की 99% सड़कें नगर निगम के अधीन हैं, इसलिए वहां भी मिलिंग अनिवार्य की जानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पीडब्ल्यूडी एक दिन में आदेश जारी कर सकता है, तो नगरीय प्रशासन विभाग को छह महीने क्यों लग रहे हैं, जबकि मिलिंग की दरें पहले से तय हैं और इसके लिए शासन की नई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

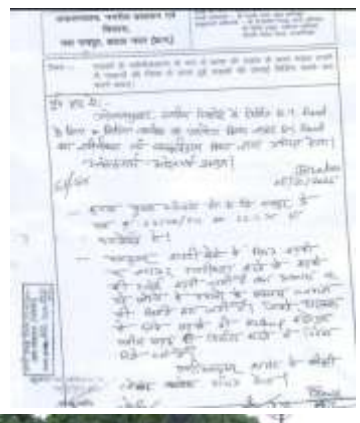

मुख्यमंत्री ने किया साइबर सतर्कता अभियान का शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर से एसबीआई साइबर सतर्कता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर लोगों से अपील की कि वे अपने बैंक खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी, पासवर्ड और ओटीपी किसी से साझा न करें तथा अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से बचें। उन्होंने कहा कि साइबर ठग आए दिन नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं और ज़रा सी लापरवाही मेहनत की कमाई पर भारी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि तकनीक ने जीवन को सरल और डिजिटल लेन-देन को तेज बनाया है, लेकिन इसके साथ साइबर अपराध भी बढ़े हैं। थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता से लोग साइबर धोखाधड़ी से बच सकते हैं। इस अभियान के तहत लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए आडियो-वीडियो संदेश, नुक्कड़ नाटक और कठपुतली नाटक के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रयास नागरिकों को साइबर अपराध से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

छत्तीसगढ़ नेट-सेट पीएचडी संघर्ष संघ का प्रदर्शन, भर्ती की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ नेट-सेट पीएचडी संघर्ष संघ ने शनिवार को रायपुर कलेक्ट्रेट गार्डन में प्रदर्शन कर राज्य सरकार से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की मांग की। संघ के पदाधिकारी और सदस्य इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की तैयारी में हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वर्तमान समय में 50 से 70 प्रतिशत तक सहायक प्राध्यापकों के पद खाली पड़े हुए हैं, जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन में शामिल 50 से अधिक अभ्यर्थियों ने कहा कि बीते छह वर्षों से इन पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है। नेट, सेट और पीएचडी डिग्रीधारी युवाओं का आरोप है कि लगातार उपेक्षा से उनमें गहरी नाराजगी और निराशा है। उन्होंने मांग की कि सरकार शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करे और विज्ञापन जारी कर योग्य अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करे। संघर्ष संघ के सदस्यों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर लगातार विभिन्न मंत्रियों और अधिकारियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं।

चार नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

16.50 लाख नकदी, लैपटॉप और नक्सली सामग्री जब्त

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गरियाबंद जिले में चार हार्डकोर माओवादियों ने रायपुर संभाग के आईजी अमरेश मिश्रा और एसपी गरियाबंद के सामने आत्मसमर्पण किया है। राज्य सरकार ने इन पर कुल 19 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। आत्मसमर्पण करने वालों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) के डीजीएन डिवीजन से जुड़े सक्रिय माओवादी आत्मसमर्पण के लिए सामने आए हैं। सरेंडर करने वालों में डीव्हीसीएम दीपक उर्फ भीमा मंडावी (₹8 लाख इनामी), एरिया कमेटी सदस्य कैलाश उर्फ भीमा भोगम (₹5 लाख इनामी), रनिता उर्फ पायकी (₹5 लाख इनामी) और सुजीता उर्फ उरें कारम (₹1 लाख इनामी) शामिल हैं।

दीपक उर्फ भीमा मंडावी: मूल निवासी सुकमा, 2008 से संगठन में सक्रिय, 2018 में एसीएम और एलजीएस कमांडर, अप्रैल 2025 में डीव्हीसीएम बनाया गया। गरियाबंद-धमतरी क्षेत्र की कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा।

कैलाश उर्फ भीमा भोगम: सुकमा निवासी, बचपन से संगठन से जुड़ा, 2014 से सीसी-मनोज के प्रोटेक्शन टीम में रहा। 2020 से 2025 तक विभिन्न जिम्मेदारियों पर रहा। कंधमाल (ओडिशा), नुआपाड़ा और बस्तर की घटनाओं में शामिल।

रनिता उर्फ पायकी: बीजापुर की निवासी, 2016 में माओवादी संगठन में शामिल हुई। 2017 से सीसी-मनोज की प्रोटेक्शन टीम का हिस्सा रही। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई माओवादी घटनाओं में सक्रिय।

80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों को मिलेगी अतिरिक्त पेंशन

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के बुजुर्ग पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के लिए राहत भरा निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा 14 अगस्त को जारी निर्देश के अनुसार अब 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को उनकी मूल पेंशन पर अतिरिक्त राशि मिलेगी।

निर्धारित प्रावधान के मुताबिक—

80 से 85 वर्ष तक : मूल पेंशन का 20% अतिरिक्त

85 से 90 वर्ष तक : मूल पेंशन का 30% अतिरिक्त

90 से 95 वर्ष तक : मूल पेंशन का 40% अतिरिक्त

95 से 100 वर्ष तक : मूल पेंशन का 50% अतिरिक्त

100 वर्ष या उससे अधिक : मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त

यह अतिरिक्त पेंशन उस कैलेंडर माह के पहले दिन से देय होगी, जिसमें पेंशनर निर्धारित आयु पूरी करता है। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी पेंशनर का जन्म 15 जनवरी 1943 को हुआ है, तो उसे एक जनवरी 2023 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा।

बीजापुर के तारलागुड़ा में करोड़ों की सट्टेबाजी, थाने से महज 500 मीटर दूर लग रहा मुर्गा बाजार

छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर मुर्गा फाइट का गोरखधंधा

बीजापुर। नक्सल प्रभावित बीजापुर जिला आमतौर पर ऑपरेशन और मुठभेड़ को लेकर सुर्खियों में रहता है, लेकिन इन दिनों यहां एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जिले के तारलागुड़ा क्षेत्र में खुलेआम मुर्गा फाइट और उस पर सट्टेबाजी हो रही है। आश्चर्यजनक यह है कि यह सबकुछ तारलागुड़ा थाना मुख्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर चल रहा है, और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं है।

मुर्गा बाजार का आयोजन

सूत्रों के अनुसार, तारलागुड़ा में सप्ताह में दो दिन - शुक्रवार और रविवार को मुर्गा बाजार सजता है। यहां वाटरप्रूफ टेंट लगाए जाते हैं ताकि मौसम का असर न पड़े। मुर्गा फाइट के दौरान न सिर्फ दांव लगते हैं बल्कि शराब और खाने-पीने का भी इंतजाम किया जाता है। शराब और चखना बेचने वालों से बाकायदा टैक्स वसूला जाता है। आयोजन स्थल पर तीन लेयर की फेंसिंग बनाई जाती है। अंदर प्रवेश करने के लिए वीआईपी टिकट लिया जाता है जिसकी कीमत 1000 रुपए प्रति व्यक्ति है।

तेलंगाना से आते वीआईपी मुर्गाबाज

इस अवैध आयोजन में तेलंगाना से बड़ी संख्या में रईस और प्रभावशाली मुर्गाबाज आते हैं। वे लग्ज़री गाड़ियों में पहुंचते हैं और एक-एक मुकाबले में लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक का दांव लगाते हैं। इस तरह का आयोजन तारलागुड़ा को सीमावर्ती 'जुए और सट्टेबाजी का अड्डा' बना चुका है।

पुलिस की चुप्पी पर सवाल

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सबकुछ थाने से आधा किलोमीटर की दूरी पर होता है। सवाल यह है कि क्या पुलिस को सचमुच इसकी जानकारी नहीं है? अगर है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्या इसमें स्थानीय स्तर पर मिलीभगत है?

संपादकीय

सुकांत राजपूत

अगर या मगर

अगर दो मंत्री बने तो मंत्री की संख्या 13 हो जाएगी जो कि अशुभ आंकड़ा माना जाता है। इस लिए अब 14 बनाने होंगे। अगर विदेश से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो 10 दिन नाराजगी और कोई अन्य स्थिति को संभालने के लिए मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति भारी पड़ सकती है। अगर अमर अग्रवाल को बनाया जाता है तो पुराने नेता धरमलाल कौशिक अजय चंद्राकर राजेश मुड़त लता उसेंडी में असंतोष बढ़ सकता है। अगर सरगुजा के राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाया जाता है तो सरगुजा संभाग से ही विष्णु देव, राम विचार नेताम, लक्ष्मी राजवाड़े और श्याम बिहारी पहले ही मंत्री है। यह भौगोलिक संतुलन के खिलाफ होगा। अगर खुशवंत साहिब को मंत्री बनाया जाता है तो अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर पहले ही वो दायित्व संभाल रहे है। ऐसे में एक व्यक्ति एक फार्मूला प्रभावित होगा, पूरा मंत्री बनाना होता तो इस पद पर पहले नहीं बनाते। अगर सभी तीनो मंत्री मैदानी इलाकों से बनाए जाएंगे तो बस्तर जैसा बड़ा संवेदनशील संभाग जहां से बीजेपी को इस बार ज्यादा समर्थन मिला वह अछूता रह जाएगा। अगर फेरबदल की जगह विस्तार किया जाता है तो जिन मंत्रियों के कामों से इंकमबेंसी पैदा हो रही है वो और बढ़ेगी। मगर पार्टी को सेकंड लाइन तैयार करना जरूरी है इसलिए नए आज्ञाकारी चेहरे को मौका मिलेगा। मगर जिन्होंने पार्टी के आदेश पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी छोड़ी उसमें धरमलाल कौशिक, विक्रम उसेंडी अब तक तल्खियां नहीं दिखाए हैं। मगर लोकसभा चुनाव में रणनीतिक रूप से जिम्मेदारी संभालने के लिए क्लस्टर प्रभारी बनाए गए थे। इसमें अहम भूमिका निभाने वाले राजेश मुड़त को अब तक कुछ मिल नहीं पाया है, उनके बारे में भी पार्टी को विचार करना होगा। मगर रायपुर से मंत्रिमंडल में किसी सदस्य को नहीं रखने की गलती भूपेश सरकार में भी हुई थी जिसकी वजह से सरकार के खिलाफ इंकमबेंसी पैदा करने का केंद्र रायपुर बना था। कमोबेश इस बार भी सत्ता और सियासत के हालात बन रहे हैं। क्योंकि हवा रायपुर से बनती है इस का भुगतान भूपेश सरकार को भी करना पड़ा था। वैसे प्रदेश भाजपा संगठन में विक्रम उसेंडी से अच्छा आदमी तो दूजा नहीं है।

विक्रम विधायक भी रहे, पूर्व मंत्री रहे, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद भी रहे और सबसे बड़ी बात जिनमें शालीनता भी है। ऐसों की अनदेखी अगर होगी तो रायपुर में सियासी दही हांड़ी मोहन भी फोड़ेंगे और बस्तर के लोग भी।

सुशील भोले

कोंदा-भैरा के गोठ

-अपन भाखा खातिर मया अउ वोकर बढ़वार खातिर पोठ उदिम कइसे करे जाथे तेकर ठउका उदाहरण अभी पश्चिम बंगाल म देखे बर मिले हे जी भैरा.

-कइसे.. उहाँ का होगे तेमा जी कोंदा?

-पश्चिम बंगाल सरकार ह पूरा राज्य भर के जम्मो सिनेमा घर मन म 'प्राइम टाइम' के बेरा म रोज क्षेत्रीय फिल्म माने बंगाली सिनेमा देखाए के आदेश निकाले हे.

-ए तो उहाँ के भाखा संस्कृति के बढ़वार के रद्दा म वाजिब म बड़का बुता ए काबर ते सिनेमा ह भाखा संस्कृति बढ़वार म पोठ भूमिका निभाथे.

-हव जी.. फेर मैं गुनथौं संगी हमर इहाँ के सत्ताधारी मन के चेत ह अइसने कब जागही?

-इहाँ तो शिक्षा के माध्यम बनाय के रद्दा ह अभी तक बने गतर के चतवारे नइ जा सके हे, त अंते-तंते मनला अउ का गुनबे?

-हमर इहाँ राजनीतिक इच्छाशक्ति के कमी जादा जनाथे संगी.

-हव कमी तो हे, फेर भाखा के जबर मयारुक बरोबर ढोंग घलो कर लेथें.. जब एक दल के मन सत्ता म होथें त दूसर दल वाले मन मटमटाए म कमी नइ करँय अउ दूसर दल के मन सत्ता म बइठ परथें त पहला वाले मन अइसने करथें.. फेर जब कहूँ सत्ता म आथें तहाँ ले सबो ल बिसर जाथें.

संवैधानिक पदों की निष्ठाओं पर उठते सवाल

पवन के. वर्मा

पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक

अब जब हम नए उपराष्ट्रपति के नामांकन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 21 जुलाई को- मानसून सत्र के ऐन पहले- रहस्यमयी तरीके से दिया गया इस्तीफा मानो भुला-सा दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है धनखड़ अभी कहां हैं, इस बारे में भी ज्यादा लोगों को खबर नहीं है। स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ था, जब किसी पदासीन उपराष्ट्रपति द्वारा पद से इस्तीफा दिया गया हो। यह कोई मामूली बात नहीं है। इससे पहले जिन उपराष्ट्रपतियों ने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया, वो सिर्फ इसलिए था, क्योंकि वे राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार थे।

देर रात अचानक दिए अपने त्यागपत्र में धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। शायद, यह सच हो सकता है। लेकिन सार्वजनिक रूप से ज्ञात तथ्य यह तो नहीं दर्शाते कि वे गम्भीर रूप से अस्वस्थ थे। उनकी हाल ही में एंजियोप्लास्टी जरूर हुई थी, किंतु वह एक सामान्य प्रक्रिया थी, और प्राणघातक नहीं थी। 74 की उम्र भी इतनी नहीं होती। इसके अलावा, इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि इस्तीफे के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया हो।

वास्तव में, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, उस दिन भी वे अस्वस्थ नहीं दिखे, बल्कि पूरी तरह सक्रिय रहे थे। राज्यसभा के सभापति के तौर पर उन्होंने दोपहर 12:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक तय की, जिसमें विपक्ष और भाजपा के नेताओं ने हिस्सा लिया।

उनका प्रतिनिधित्व सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कर रहे थे। बैठक में शामिल किसी भी व्यक्ति ने यह संकेत नहीं दिया कि धनखड़ बीमार लग रहे थे, या अपनी सामान्य ऊर्जा से कम थे। बैठक बेनतीजा रही और शाम 4:30 बजे फिर से शुरू होने वाली थी। लेकिन जब बैठक फिर से शुरू हुई, तो इस बार उसमें एक बड़ा अंतर था। नड्डा और रिजिजू इसमें शामिल नहीं हुए। उसी शाम धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया।

स्पष्ट है कि अचानक हुए इस घटनाक्रम के पीछे सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी ही नहीं, और भी कारण रहे होंगे। खासकर इसलिए क्योंकि धनखड़ के कार्यालय ने अगले हफ्ते उनकी सार्वजनिक व्यस्तताओं की घोषणा कर दी थी। फिर देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा अचानक ऐसा निर्णय लेने की क्या वजह थी? उनके कार्यकाल में दो वर्ष भी शेष थे।

इतना तो निश्चित है कि अपने कार्यकाल के दौरान धनखड़ ऐसे उपराष्ट्रपति रहे थे, जिन्होंने यथासम्भव सत्ताधारी दल की अपेक्षाओं का पालन किया, भले ही वे ऐसा करने के लिए बाध्य न रहे हों। इससे पहले,

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ लगातार टकराव की स्थिति में रहे थे। उनकी यह बात सराही गई होगी। शायद पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने की उनकी जुझारू भूमिका के लिए ही उन्हें उपराष्ट्रपति पद से पुरस्कृत किया गया हो। हालांकि ऐसा उनकी योग्यता के आधार पर भी हो सकता था, क्योंकि वे संविधान के अच्छे जानकार और एक प्रतिष्ठित वकील थे।

राज्यसभा के सभापति के रूप में, सत्ता पक्ष के प्रति उनके झुकाव के चलते ही विपक्ष ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह भी हमारे संसदीय इतिहास में पहली बार होने वाली घटना थी। उन्होंने विपक्षी सदस्यों को निष्कासित किया था और सदन में संघ की भी प्रशंसा की थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि त्यागपत्र देने की नौबत आई? ऐसी अटकलें हैं कि जब उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर यादव- जिन्होंने कथित तौर पर अशोभनीय साम्प्रदायिक बयान दिए थे- के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किया तो यह बात पार्टी नेतृत्व को पसंद नहीं आई।

यह भी कहा जा रहा है कि उनकी "गलती' न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करना था, जिसका श्रेय भाजपा लेना चाहती थी। या फिर यह कि संसदीय सर्वोच्चता बनाम न्यायपालिका के मामले पर उनका तीखा रुख सरकार को एक असहज स्थति में डाल देने वाला था। जो भी हो, यह तो साफ है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया, जिससे उन्हें पूर्व में उन्हें उपकृत करने वाली पार्टी का ही कोपभाजन बनना पड़ा।

पर इस सबमें वास्तविक चिंताजनक मुद्दा एक गैर-राजनीतिक संवैधानिक पद की निष्ठा का है। अगर ऐसे किसी पद पर आसीन व्यक्ति तभी पदाधिकारी रह सकता है, जब वह गैर-राजनीतिक होने की अपनी शपथ का निर्वाह न करे तो स्वतंत्र संस्थाओं का नेतृत्व करने वाले दूसरे लोगों का क्या? और हमारे लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं? पूर्व उपराष्ट्रपति वाले मामले में मुद्दा संवैधानिक पद की निष्ठा का है। अगर ऐसे किसी पद पर आसीन व्यक्ति तभी पदाधिकारी रह सकता है, जब वह गैर-राजनीतिक न रह पाए तो स्वतंत्र संस्थाओं का नेतृत्व करने वालों का क्या? **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

नई नहीं हैं मतदाता-सूची में गड़बड़ियां

शीला भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार

राहुल गांधी उत्साह से भरे हैं। वे मानने लगे हैं कि मोदी का युग अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों में से चुनिंदा मतदाताओं का ब्योरा पेश करते हुए बताया कि कैसे बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा मतदाता 'चोरी-चुपके' जोड़ दिए गए। वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भाजपा ने यह अपने फायदे के लिए किया है और वे यह आरोप भी लगाते हैं कि आयोग ने वोटों की 'चोरी' में भाजपा के साथ मिलीभगत की है। लोकतंत्र में इससे गंभीर आरोप शायद ही कोई लगा सकता है। जबकि सच्चाई यह है कि दशकों से सभी राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार मौका मिलने पर वोटर-लिस्ट में मतदाताओं के नाम जोड़ने, घटाने और हटाने का खेल खेलते आ रहे हैं।

आज के कोलाहल भरे राजनीतिक माहौल में अगर कांग्रेस भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाती है तो समझ आता है, लेकिन राहुल ने सीधे चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन क्यों छेड़ दिया है? राहुल मतदाता-सूची के वीडियो फुटेज और डिजिटल प्रतियों की मांग कर रहे हैं। आयोग ने फैसलों और कानूनों का हवाला देते हुए कहा है कि डिजिटल प्रतियां उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाती हैं। मतदान केंद्रों के वीडियो फुटेज 45 दिनों तक ही रखे जाते हैं, जब तक कि कोई उम्मीदवार समीक्षा याचिका दायर न करे। आयोग का कहना है कि एक लाख मतदान-केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा में एक लाख दिन लगेंगे- यानी लगभग 273 साल।

कानून तो यही कहता है कि किसी भी दल को मतदान-प्रक्रिया या मतदाता-सूची में विसंगति पाए जाने पर नतीजों के 45 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। लेकिन राहुल ने आयोग के आंकड़ों की व्याख्या करने में इससे ज्यादा समय ले लिया है। आयोग ने कहा है कि अगर राहुल को अपने तथ्यों पर विश्वास है, तो उन्हें नियम 20(3)(बी) के अनुसार संदिग्ध मतदाताओं के खिलाफ दावे पेश करने और शपथ लेकर घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। राहुल ने इससे इनकार किया है। इससे पता चलता है यह राजनीतिक लड़ाई ज्यादा है। अलबत्ता राहुल ने जो मुद्दा उठाया है, वो महत्वपूर्ण है। वे उस बात का खुलासा कर रहे हैं, जो दशकों से विवादित और गंभीर चिंता का विषय रही है। चुनावों की पूर्व संध्या पर ताकतवर उम्मीदवारों के 'पोलिंग-एजेंट' फर्जी मतदान कराने के कई तरीके ढूंढ लेते हैं।

वे मतदाता-सूची की जानकारी का दुरुपयोग करते हैं। मतदान के दिन से कई हफ्तों पहले वे अपने निर्वाचन-क्षेत्र के सभी मतदाताओं पर नजर रखते हैं और पता लगाते हैं कि कितने मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, कितने बाहर चले गए हैं, कितने नए मतदाता बने हैं आदि। अपने निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाता-सूची पर पूरी पकड़ के बिना किसी भी उम्मीदवार के लिए चुनाव जीतना संभव नहीं है। भारत में 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। महानगरों में लगभग 30 लाख लोग ऐसे हैं, जिनके पास अपना पता नहीं है। मतदाता पहचान-पत्र पाने के लिए वे उस व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं, जो उन्हें किसी 'घर के पते' का इस्तेमाल करने की अनुमति देता हो। देश में निर्माण-क्षेत्र में लगभग एक करोड़ असंगठित मजदूर निर्माण स्थल पर या उसके आस-पास रहते हैं। चुनाव के समय वे अपने लिए 'उपलब्ध' पते का इस्तेमाल करते हैं। भारत में 45 करोड़ से ज्यादा लोग प्रवासी हैं। इन्हें पुराने घर का नाम हटाकर नए घर का पता जोड़ना होता है। यह प्रक्रिया मजदूरों के लिए कठिन है। उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट मतदाताओं की गतिविधियों पर नजर रखते हैं।

यह थकाऊ और महंगा काम है। 2008 में, यूपी में मतदाता-सूची के पुनरीक्षण के दौरान मृत और डुप्लिकेट मतदाताओं के 21.13 लाख वोट हटा दिए गए थे। उस वर्ष संशोधन के बाद 61.69 लाख नाम जोड़े गए और 78.01 लाख नाम हटाए गए। उस समय यूपी की जनसंख्या 11 करोड़ थी, जो अब 24 करोड़ से ज्यादा है। घर-घर जाकर सर्वेक्षण की व्यवस्था भी बंद कर दी गई है। एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार, 'यह पाया गया है कि यदि हर साल घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया जाता है, तो मतदाता सूची में 3 से 4% विसंगतियां आ जाती हैं।' यह बड़ी संख्या है। यही कारण है कि चुनाव आयोग के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण बेहद जरूरी हो गया है। भारत का आम आदमी चुनाव आयोग, संसद और न्यायालय में श्रद्धा रखता है, चाहे वे जितने कमजोर हो जाएं। राहुल इस श्रद्धा को हिला नहीं सकते, इसलिए इस आंदोलन को किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा सकते। अगर राहुल गांधी को बेंगलुरु में एक ही कमरे में 80 मतदाता मिलते हैं तो भारत में यह बिल्कुल सामान्य बात है। उन्हें पश्चिम बंगाल, मुंबई और सूरत में भी एक कमरे या एक झुग्गी बस्ती में मतदाताओं का ऐसा ही जमावड़ा मिलेगा।

साप्ताहिक शहर सत्ता

7 दिन में हलफनामा दें या देश से माफी मांगें

राहुल गांधी को चुनाव आयोग की दो टूक, कहा- कोई तीसरा विकल्प नहीं

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने रविवार (17 अगस्त 2025) को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए गए आरोपों पर दो टूक जवाब दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं. इस तरह के गलत आंकड़े देना और ये कहना कि ये पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने दो बार वोट दिया है. इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए."

मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए दो टूक कहा, "हलफनामा देना होगा या देश से मांफी मांगनी होगी. तीसरा विकल्प नहीं है. अगर सात दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये होगी कि ये सारे आरोप निराधार है." उन्होंने कहा, "बिना किसी सबूत के योग्य वोटर का नाम नहीं कटेगा. चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा है."मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या और सारे मीडिया के सामने ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने दो बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा. इतने आरोपों के बाद चुनाव आयोग शांत रहे ऐसा संभव ही नहीं. उन्हें हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी." उन्होंने कहा, "पिछले 20 सालों में SIR नहीं किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है. राजनीतिक दलों से कई शिकायतें मिलने के बाद SIR किया जा रहा है.।

चुनाव आयोग ने दिया हर आरोप का जवाब

- आयोग ने कहा कि जब देश के 7 करोड़ से अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं तो न तो चुनाव आयोग और न ही मतदाताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जा सकता है.
- मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे कहा, 'हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की तस्वीरें बिना उनकी अनुमति के मीडिया के सामने पेश की गईं. उन पर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया. क्या चुनाव आयोग को मतदाताओं, उनकी माताओं, बहुओं या बेटियों के सीसीटीवी फुटेज साझा करने चाहिए? मतदाता सूची में जिनके नाम होते हैं, वे ही अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट डालते हैं.'
- उन्होंने कहा, 'लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया में एक करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं. इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई मतदाता वोट की चोरी कर सकता है?
- ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'कुछ मतदाताओं की ओर से दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला.
- आयोग ने कहा, 'मशीन द्वारा पढ़े जाने वाली मतदाता सूची पर प्रतिबंध है. चुनाव आयोग का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद है और 2019 से है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सवाल खड़े करते हुए कहा, 'क्या आप जानते हैं कि इस देश में करोड़ों लोगों के पते के आगे जीरो नंबर लगा है, क्यों? दरअसल पंचायत या नगरपालिका ने उनके घर को कोई नंबर नहीं दिया है.'

बिहार से शुरु हुई 'वोटर अधिकार यात्रा'

पटना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को दावा किया कि मोदी सरकार ने दबाव में आकर जाति जनगणना की घोषणा की है, लेकिन वह न तो "सच्ची" जाति जनगणना कराएगी और न ही आरक्षण पर लगी 50% की सीमा को हटाएगी. बिहार के सासाराम में 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने यह बात कही. इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश साहनी भी शामिल हुए. राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, "हमने संसद में कहा था कि हमें जाति जनगणना चाहिए और आरक्षण पर 50% की सीमा की दीवार को खत्म किया जाना चाहिए. मैंने यह बात प्रधानमंत्री मोदी के सामने कही थी."

सच्ची जाति जनगणना नहीं कराएगी सरकार- राहुल

उन्होंने आगे कहा, "भाजपा और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना की घोषणा तो कर दी, लेकिन मैं जानता हूं कि वे न तो सच्ची जाति जनगणना कराएंगे और न ही आरक्षण पर 50% की सीमा की दीवार को कभी हटाएंगे।"

भारत को घेरने चले थे ट्रंप पुतिन ने चौपट किया प्लान

नई दिल्ली। अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपनी आक्रामक रणनीतियों के लिए जाने जाते रहे हैं. इस बार उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अलास्का बुलाकर एक बड़ा खेल खेलने की कोशिश की. उनकी योजना थी कि भारत को चारों ओर से दबाव में लाया जाए, चाहे वह पाकिस्तान कार्ड हो, व्यापार समझौते का दबाव हो या फिर अंतरराष्ट्रीय अदालतों में मुद्दा उठाना, लेकिन यह कोशिश उसी वक्त ध्वस्त हो गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति ने हालात पूरी तरह पलट दिए.

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Trade Deal) पर बातचीत चल रही थी. पांच दौर की वार्ता पूरी भी हो चुकी थी. लेकिन छठे दौर की बैठक, जो अगस्त के अंत में दिल्ली में होने वाली थी, उसे अचानक स्थगित कर दिया गया. अमेरिका का मकसद था कि भारत रूस से अपनी ऊर्जा और रक्षा खरीद कम करे और अमेरिकी शर्तों को मान ले. लेकिन जब मोदी सरकार ने झुकने से इनकार किया, तब अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की. ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अपने घर बुलाया. वहां से भारत के खिलाफ जहर उगला गया परमाणु हमले की धमकी से लेकर सिंधु जल संधि को तोड़ने तक की बातें सामने आईं. अमेरिका की धरती पर खड़े होकर पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने भारत को खुली धमकियां दीं. अमेरिकी राजनीतिक हलकों में इस पर सवाल उठे कि कैसे ट्रंप ने यह बयानबाजी होने दी, लेकिन ट्रंप की चुप्पी यह संकेत दे रही थी कि वे इस खेल का हिस्सा हैं और भारत को झुकाना चाहते हैं.हालांकि भारत ने इस पर तीखा जवाब दिया और पाकिस्तान की रणनीति धरी की धरी रह गई.

पुतिन से मुलाकात और ट्रंप की नाकामी

ट्रंप को उम्मीद थी कि पुतिन भारत पर बयान देंगे और रूस-भारत संबंधों में दरार डालने का माहौल बनेगा. लेकिन हुआ इसका उल्टा. पुतिन ने भारत पर कोई बयान नहीं दिया. मोदी और पुतिन की दोस्ती और सामरिक साझेदारी पहले की तरह मजबूत रही. ट्रंप की पूरी रणनीति चौपट हो गई क्योंकि उनका मकसद भारत को रूस से अलग करना था. यानी ट्रंप का खेल उन्हीं पर उल्टा पड़ गया. मोदी सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम में स्पष्ट संदेश दिया कि भारत किसी दबाव में नहीं झुकेगा. रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सहयोग जारी रहेगा.पाकिस्तान की धमकियों का जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा.

जम्मू-कश्मीर: कठुआ में बादल फटा, 7 लोगों की मौत

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में भारी बारिश के बीच बादल फटने की घटना सामने आई है. घाटी क्षेत्र में बादल फटने से कई घर मलबे और बाढ़ के पानी में दब गए. जम्मू-पठानकोट नेशनल हाइवे को भी नुकसान की रिपोर्ट है. राहत और बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. अब तक सात लोगों को मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिसमें पांच नाबालिग हैं. अधिकारियों ने बताया कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात कठुआ जिले के राजबाग इलाके के जॉड घाटी गांव में बादल फटा. इस घटना से गांव का बाकी इलाकों से संपर्क टूट गया और जमीन और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है. हालांकि शुरुआत में किसी जनहानि की रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन बाद में सात लोगों की मौत और छह लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस और SDRF की संयुक्त टीम को तुरंत गांव भेजा गया. अधिकारियों ने कहा कि स्थिति की निगरानी की जा रही है।

रूस के आगे 'सरेंडर' नहीं करेंगे जेलेंस्की

कीव। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की बैठक के बाद से यूक्रेन में जारी युद्ध के अंत को लेकर संभावनाएं तलाशी जा रही है. युक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की सोमवार (18 अगस्त 2025) को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ शांति वार्ता में शामिल होंगे. यूक्रेन के भविष्य का फैसले को लेकर होने वाली बैठक में यूरोपीय नेता भी शामिल होंगे.

यूरोपीय आयोग की प्रमुख युरसुला वॉन डेर लेयेन के साथ-साथ जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो और नाटो महासचिव मार्क रुटे, ब्रिट्रेन के पीएम कीर स्टार्मर,इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी इस मीटिंग में जेलेंस्की के साथ होंगे. फ्रेडरिक मर्ज और इमैनुएल मैक्रो यूरोपीय यूनियन की ओर से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिनका उद्देश्य यूक्रेन में शांति समझौते की रक्षा के लिए देशों को एक साथ लाना है. जर्मनी की सरकार के मुताबिक इस बैठक में मुख्य रूप से सुरक्षा गारंटी, क्षेत्रीय मुद्दों और रूस की आक्रामकता के खिलाफ यूक्रेन को जारी समर्थन पर चर्चा होगी.पुतिन के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने सीजफायर की मांग को छोड़ दिया है. उनका मानना है कि तत्काल शांति समझौता के तहत सीजफायर से भी अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं. ट्रंप के अनुसार अगर जेलेंस्की रूस को डोनबास का पूरा इलाका सौंप दें तो तत्काल शांति बहाल की जा सकती है. जेलेंस्की ने रूस को जमीन देने से साफ मना कर दिया है और इसमें यूरोपीय देशों ने उनका साथ भी दिया।

NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन

नई दिल्ली: NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम फाइनल हो गया है। सीपी राधाकृष्णन NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात की जानकारी दी है। नड्डा ने बताया, "पीएम मोदी की मौजूदगी में संसदीय बोर्ड की मीटिंग में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है।"

कौन हैं सीपी राधाकृष्णन?

सीपी राधाकृष्णन मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं और बीजेपी, RSS और जनसंघ के पुराने नेता रहे हैं। वह वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले वह झारखंड के राज्यपाल थे और उनके पास तेलंगाना के भी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार था। इसके अलावा वह पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन कोयंबटूर (तमिलनाडु) से लोकसभा सांसद रह चुके हैं और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे हैं। 16 वर्ष की आयु में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और जनसंघ से जुड़ गए थे। दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु और केरल में भाजपा को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सीपी राधाकृष्णन OBC हैं और गाउंडर जाति से हैं। गाउंडर में एक उपजाति है जिसका नाम कोंगु वेल्लालर है। राधाकृष्णन इस उपजाति से हैं। ये उपजाति मूलतः खेती किसानी से जुड़ी है। पश्चिमी तमिलनाडु जिसे कोंगु रीजन भी कहा जाता है वहां इस जाति का दबदबा है। अन्नामलई और AIADMK नेता E पलनीस्वामी भी इसी जाति से हैं। AIADMK के साथ गठबंधन के लिए EPS के दबाव में आकर जब BJP ने, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अन्नामलई को बदल दिया तब से ये चर्चा थी कि इस उपजाति के वोट BJP से दूर जा सकते हैं। तमिलनाडु में अगले साल चुनाव हैं। ऐसे में CPR को उपराष्ट्रपति बनाने का कदम एक डेमेज कंट्रोल है।

हम विपक्ष से भी बात करेंगे: नड्डा

जेपी नड्डा ने कहा, "हम विपक्ष से भी बात करेंगे। हमें उनका समर्थन भी प्राप्त करना चाहिए ताकि हम मिलकर उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुनाव सुनिश्चित कर सकें। जैसा कि हमने पहले कहा, हम उनके संपर्क में हैं और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने पहले भी उनसे संपर्क किया है और अब भी हम उनके संपर्क में रहेंगे और हमारे सभी एनडीए सहयोगियों ने हमारा समर्थन किया है। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं।"

सूर्या खेलेंगे एशिया कप

टीम इंडिया के एलान से पहले पास किया फिटनेस टेस्ट

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम और उसके फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आई है. टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. वह 2025 एशिया कप में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. कुछ वक्त पहले सूर्या ने स्पोर्ट्स हार्निया की सर्जरी कराई थी. इसके बाद से वह रिहैब से गुजर रहे थे. भारत की एशिया कप टीम चुनने के लिए अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति की बैठक से पहले टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बेंगलुरु स्थित 'बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. सूर्यकुमार आखिरी बार आईपीएल में खेले थे और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुने गए. इस आक्रामक बल्लेबाज ने जून में जर्मनी के म्यूनिख में पेट के निचले दाहिने हिस्से में 'स्पोर्ट्स हर्निया' की सर्जरी करवाई थी. बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया, "सर्जरी के बाद वापसी (रिटर्न टू प्ले-आरटीपी) से पहले फिटनेस टेस्ट अनिवार्य है. सूर्यकुमार ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है." बता दें कि सर्जरी के बाद सूर्यकुमार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, "पेट के निचले दाहिने हिस्से में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी करवाई. यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सर्जरी के बाद मैं पहले से ही ठीक हो रहा हूं. वापसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं."

9 सितंबर से होगा एशिया कप

बता दें कि 2025 एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा. इसका फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा. इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें हिस्सा लेंगी. इन टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. 2025 एशिया कप के मैच आबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे. टीम इंडिया टूर्नामेंट में अपना पहला मैच 10 सितंबर को खेलेगी.

3 बार हो सकता है पाक से मैच

2025 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा. यह लीग स्टेज का मैच होगा. दोनों टीमें 21 सितंबर को सुपर-4 राउंड में भी भिड़ सकती हैं. इसके बाद अगर भारत और पाकिस्तान दोनों फाइनल में प्रवेश करते हैं तो एक बार फिर दोनों के बीच मैच होगा. इस तरह 2025 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैच खेले जा सकते हैं.

45 साल तक वनडे खेल सकते हैं रोहितः योगराज

नई दिल्ली। भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह का मानना है कि रोहित शर्मा भारत के लिए 45 साल की उम्र तक खेल सकते हैं. बता दें कि रोहित ने पिछले साल टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था. वहीं इस साल मई में रोहित ने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है. रोहित भारत के लिए बस अब वनडे मैच खेलते हुए दिखेंगे.

योगराज ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान रोहित के आलोचकों को जमकर लताड़ा और कहा कि उन्हें अभी भारत के लिए 5 साल और खेलने की जरुरत है. योगराज ने कहा, "रोहित ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनके बारे में कई लोग बकवास करते हैं. जिस तरह से वह बल्लेबाजी करता है, उसकी बल्लेबाजी एक तरफ होती है और बाकी टीम की बल्लेबाजी दूसरी तरफ. उसकी पारी एक तरफ और बाकी दुनिया दूसरी तरफ, यही उसका क्लास है. आप कह सकते हो कि 'रोहित, हमें तुम्हारी 5 साल और जरूरत है. उसके अंदर 45 साल की उम्र तक खेलने का क्लास है." योगराज ने रोहित को फिटनेस पर काम करने की सलाह दी. योगराज ने कहा, "देश के लिए और करो, फिटनेस पर काम करो. उसे रोज 10 किलोमीटर दौड़ाओ, चार लोग फिटनेस के लिए उसके पीछे लगाओ. अगर वो चाहे तो 45 साल तक खेल सकता है."

घरेलू क्रिकेट खेलने की सलाह

योगराज ने रोहित को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की सलाह दी. योगराज ने कहा, "मेरा मानना है कि खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए, जितना ज्यादा खेलोगे उतना फिट रहोगे. फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे मिला? रोहित शर्मा को. तो बातें वही करो जो तुम्हें आती हैं. अगर तुम्हें उसके खेल और फिटनेस पर कुछ कहना है, तो पहले खुद किसी लेवल पर खेलकर आओ. क्या तुम्हें ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती?"

RBI से रेपो रेट में राहत के बावजूद बढ़ाया होम लोन

नई दिल्ली। घर खरीदने का प्लान कर रहे लोगों के सपनों को देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने झटका दिया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने होम लोन पर ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला किया है. बैंक ने ब्याज दरों के ऊपरी बैंड में 25 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया है. पहले एसबीआई का होम लोन ब्याज 7.50% से 8.45% के बीच था, लेकिन अब यह बढ़कर 7.50% से 8.70% के बीच हो गया है. यानी निचली सीमा वही रखी गई है, जबकि ऊपरी सीमा बढ़ाई गई है. गौरतलब है कि जुलाई में भी एसबीआई का ब्याज दर रेंज 7.50% से 8.45% था. इस नए बदलाव के बाद अब नए ग्राहकों को 7.50% से 8.70% तक ब्याज चुकाना होगा. जुलाई के आखिर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी ब्याज दरें बढ़ाकर 7.35% से 7.45% कर दी थीं. वहीं निजी बैंकों में आईसीआईसीआई 8%, एचडीएफसी 7.90% और एक्सिस बैंक 8.35% न्यूनतम ब्याज दर पर होम लोन उपलब्ध करा रहे हैं।

चेक जमा होने के बाद चंद घंटों में आएगा अकाउंट में पैसा

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में चेक जमा करने के नियमों में बदलाव करते हुए करोड़ों ग्राहकों को राहत दी है. इससे उन्हें फायदा होगा, जो आमतौर पर चेक से पेमेंट करते हैं. हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम में चेक क्लीयरेंस में लंबा वक्त लगता है. यानी कि चेक से पेमेंट करने पर अकाउंट में पैसे आने में 2-3 दिन का वक्त लग जाता है. इस देरी से उन लोगों या कारोबारियों को दिक्कतें होती हैं, जो अमूमन पर चेक से पेमेंट देते या लेते हैं. हालांकि, अब ऐसा नहीं होगा.

क्लियरेंस सिस्टम में आएगी तेजी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक तेज क्लियरेंस सिस्टम लाने जा रहा है. इससे चेक जमा कराने के कुछ ही घंटों बाद अकाउंट में पैसा आ जाएगा. 4 अक्टूबर, 2025 से चेक क्लियरेंस प्रॉसेस में लगने वाला समय काफी हद तक कम हो जाएगा. यह बदलाव चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत होगा. जहां अब तक चेक क्लीयर होने में T+1 यानी कि अगले वर्किंग डे तक का वक्त लगता था. अगर चेक दूसरे बैंक का हो तो तीन दिन तक का भी समय लग जाता है. वहीं, अब अब पूरा क्लीयरेंस प्रॉसेस कुछ ही घंटों में सिमट कर रह जाएगा. RBI के सर्कुलर के मुताबिक, यह नया सिस्टम 'Continuous Clearing and Settlement on Realisation' के नाम से जाना जाएगा. यानी कि बैंकों में कामकाज के दौरान लगातार क्लीयरिंग होती रहेगी. चूंकि अब तक चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत चेक बैच में प्रॉसेस किए जाते थे इसलिए क्लीयरेंस में भी वक्त लग जाता था।

भारत दौरे पर आएंगे मेसी

नई दिल्ली। दुनिया के महानतम फुटबॉलर्स में शुमार लियोनेल मेसी जल्द ही भारत आने वाले हैं. इवेंट प्रमोटर सतद्रु दत्ता ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि मेसी का तीन शहरों का 'GOAT Tour of India 2025' 12 दिसंबर से कोलकाता से शुरू होगा. इसके बाद वे अहमदाबाद और मुंबई जाएंगे, और 15 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. मेसी का 2011 के बाद यह पहला भारत दौरा होगा. इस दौरान मेसी स्पेशल इवेंट्स, कॉन्सर्ट और फुटबॉल मैच के जरिए भारतीय फैन्स से जुड़ेंगे. दत्ता ने शुक्रवार को कंफर्म कर दिया कि मेसी इंडिया टूर पर आएंगे. दत्ता ने पीटीआई को बताया, "मुझे अनुमति मिल गई और फिर मैंने इसे आधिकारिक तौर पर (सोशल मीडिया पर) घोषित कर दिया. मेसी 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच किसी भी दिन अपने टूर का आधिकारिक पोस्टर, जिसमें सभी डिटेल्स और एक छोटा सा परिचय होगा, पोस्ट करेंगे." मेसी 12 दिसंबर की रात को कोलकाता पहुंचेंगे, जहां उनका सबसे लंबा स्टे होगा.

EPFO 3.0 के ऐप की जिम्मेदारी टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो को

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO 3.0 के नाम से एक नया ऐप लॉन्च करने जा रहा है. इस डिजिटली एडवांस्ड आईटी सिस्टम को बनाने और इसके रखरखाव के लिए ईपीएफओ ने देश की तीन सबसे बड़ी आईटी कंपनियों - टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो - को चुना है. 12 अगस्त को जारी एक सर्कुलर में इसकी जानकारी दी गई. इससे पहले, 16 जून, 2025 को ईपीएफओ की तरफ से बड़े पैमाने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म को मैनेज करने में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनियों को एक Expression of Interest (EOI) भेजा गया था. सभी आवेदनों की समीक्षा करने के बाद ईपीएफओ ने TCS, Infosys और विप्रो को चुना. EPFO 3.0 को लॉन्च करने का एक ही मकसद है, इसे पहले के मुकाबले और ज्यादा मॉर्डन व एडवांस बनाना है. इसके शुरू होने से लाखों सब्सक्राइबर्स को EPFO की बेहतर सेवा मिलेगी।

'तुरुप का पत्ता' साबित हो सकता है जीएसटी रिफॉर्म्स

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में जीएसटी सुधारों का बड़ा ऐलान किया. पीएम मोदी की घोषणा के बाद वित्त मंत्रालय ने भी यह स्पष्ट किया कि सरकार फिलहाल जीएसटी ढांचे को सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अधिकारियों का मानना है कि यह सुधार भविष्य में भारत को "सिंगल टैक्स सिस्टम" की ओर ले जाएगा और वर्ष 2047 तक देश में एक समान टैक्स दर लागू हो सकती है.

2047 तक सिंगल टैक्स सिस्टम

फिलहाल जीएसटी में चार स्लैब हैं—5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत. नए प्रस्ताव के तहत 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब को खत्म कर दिया जाएगा. इसके बाद ज़्यादातर वस्तुएँ 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दर में समा जाएंगी. वहीं, लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक विशेष 40 प्रतिशत टैक्स दर रखने का सुझाव दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगा और उपभोक्ताओं को टैक्स के बोझ से राहत मिलेगी. इसे "नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी" कहा जा रहा है, क्योंकि इसे भारत के आर्थिक सुधारों की श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

दिवाली तक नए जीएसटी रिफॉर्म्स

सरकार चाहती है कि दिवाली तक यह नई व्यवस्था लागू हो जाए. इसके लिए केंद्र ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह को प्रस्ताव भेजा है. यह समूह प्रस्ताव का अध्ययन कर अपनी अनुशंसा सितंबर में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में रखेगा. अगर परिषद इसे मंज़ूरी देती है, तो दिवाली से पहले उपभोक्ताओं को कई वस्तुएँ सस्ती मिलना शुरू हो सकती हैं.वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, जब यह नई व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाएगी और भारत विकसित देशों की श्रेणी में पहुंचेगा, तब सरकार एक ही दर वाला जीएसटी (Single Tax Slab) लागू करने पर विचार कर सकती है. उन्होंने कहा कि यह मॉडल विकसित देशों के लिए उपयुक्त रहता है, क्योंकि वहां नागरिकों की आमदनी और खर्च करने की क्षमता लगभग समान होती है. हालांकि, अभी भारत के लिए यह सही समय नहीं है.

हफ्तेभर में 1800 रुपये से ज्यादा सस्ता हुआ सोना

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में टैरिफ को लेकर बनी अनिश्चितताओं के बावजूद क्रूड ऑयल की लगातार कम हो रही कीमतों के बीच सोने में हफ्ते भर में करीब 1800 रुपये से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है. 24 कैरेट सोना पिछले सात दिनों में जहां 1,860 रुपये सस्ता हुआ, वहीं 22 कैरेट सोने के भाव में भी 1,700 रुपये तक की कमी देखी गई है.देशभर में आज यानी 17 अगस्त 2025 को 24 कैरेट सोना औसतन 1,01,180 रुपये प्रति 10 ग्राम पर और 22 कैरेट सोना 92,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में कीमतें इससे थोड़ी अधिक हैं. यहां 24 कैरेट सोना 1,01,330 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 92,900 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से बिक रहा है. इसके साथ ही, अन्य महानगर जैसे कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 24 कैरेट सोना जहां 1,01,180 रुपये तो वहीं 22 कैरेट सोना 92,750 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

3 हजार में 200 बार टोल पार

ओडिशा सीमा से महाराष्ट्र जाने तक अब 590 नहीं, सिर्फ 90 रुपये खर्च

रायपुर। 15 अगस्त से नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स में बड़ी राहत मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए नई स्कीम लागू की है। इसके तहत यदि कोई वाहन चालक अपने फास्टैग में ₹3000 का रिचार्ज करता है तो उसे एक साल की अवधि में 200 बार टोल प्लाजा पार करने की सुविधा मिलेगी।

590 की जगह सिर्फ 90 रुपये

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के रीजनल ऑफिसर प्रदीप कुमार लाल ने बताया कि यह सुविधा किसी भी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर लागू होगी। इसका लाभ यह होगा कि वाहन चालक चाहे जिस दर वाले टोल प्लाजा से गुजरे, हर क्रॉसिंग केवल एक एंट्री मानी जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा— "अगर कोई वाहन छत्तीसगढ़ से ओडिशा बॉर्डर से लेकर महाराष्ट्र बॉर्डर तक जाता है तो फिलहाल उसे ₹590 का टोल देना पड़ता है। लेकिन इस योजना का इस्तेमाल करने पर वही यात्रा महज ₹90 में पूरी हो सकेगी।"

नियम और शर्तें

- रिचार्ज की वैधता एक साल होगी।
- एक साल के भीतर 200 पारियां पूरी करनी होंगी, अन्यथा शेष राशि लैप्स हो जाएगी।
- टोल की राशि चाहे 65 रुपये हो या 175 रुपये, सभी को एक ही क्रॉसिंग माना जाएगा।
- रिचार्ज केवल NHAI की 'मार्ग यात्रा' ऐप या आधिकारिक वेबसाइट से ही किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ में 23 टोल प्लाजा पर लागू

प्रदीप कुमार लाल ने बताया कि यह योजना केवल नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर लागू होगी। राज्य मार्ग (स्टेट हाइवे) पर यह सुविधा नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ में कुल 23 टोल प्लाजा हैं, जहां यह नियम लागू होगा।

सरकार को होगा घाटा, जनता को राहत

इस योजना से सरकार को निजी वाहनों से मिलने वाले राजस्व में कमी होगी। प्रदीप कुमार लाल ने कहा— "निश्चित तौर पर गवर्नमेंट को कुछ राजस्व नुकसान होगा, लेकिन आम जनता को सुविधा मिलना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है।"

नवा रायपुर में 128 बाइक और 6 कार जब्त

रायपुर। स्वतंत्रता दिवस पर नवा रायपुर की सड़कों को स्टंट का अखाड़ा बनाने पहुंचे बाइकर्स और कार ड्राइवरों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने घेराबंदी कर 128 बाइक और 6 कार जब्त कर लीं। आरोपियों पर तेज रफ्तार, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने, बिना नंबर प्लेट और दस्तावेजों की कमी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।

एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह के आदेश पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात डॉ. प्रशांत शुक्ला और एएसपी अटल नगर विवेक शुक्ला के मार्गदर्शन में बनाई गई विशेष योजना के तहत डीएसपी सतीश ठाकुर और गुरजीत सिंह के नेतृत्व में 40 सदस्यीय टीम ने नवा रायपुर की सड़कों पर घेराबंदी की। पकड़े गए वाहनों को थाना राखी, मंदिर हसौद और अटल नगर यातायात थानों में रखा गया है। कार्रवाई के दौरान एक युवक स्टंट करते समय बाइक से गिर गया। पुलिस ने तत्काल एंबुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसके हाथ में फ्रैक्चर की पुष्टि की। पुलिस जांच में सामने आया है कि बाइकर्स गैंग इंटरनेट मीडिया पर रील बनाने और वायरल करने के लिए स्टंट करता है। इनकी नकल करते हुए कई युवा जोखिम उठाते हैं, जिससे गंभीर हादसों की आशंका बनी रहती है।

सीएम साय ने कहा; पटवारी ग्रामीण राजस्व व्यवस्था की रीढ़

शहर सत्ता/रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर पटवारी कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए 7.70 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे कार्य में सहूलियत मिलेगी बल्कि आम जनता को राजस्व सेवाएं अब और तेजी व पारदर्शिता से उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि पटवारी हमारी ग्रामीण राजस्व व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता है। इससे उनके कार्य करने की परिस्थितियाँ बेहतर होंगी और जनता को त्वरित सेवा मिलेगी।

राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा सरकार ने पटवारियों की जायज़ मांगों को स्वीकार करते हुए वित्तीय स्वीकृति दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की मांग पत्रक में सम्मिलित बिंदुओं पर विचार करते हुए पटवारियों के लिए विभिन्न मदों में राशि आबंटित की गई है। इसमें कार्यालय संचालन, आवश्यक संसाधन एवं सुविधा विस्तार के लिए यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस निर्णय से कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम जनता को और अधिक सुगम सेवाएँ मिलेंगी। इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।

प्रदेशभर के पटवारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला ऐतिहासिक कदम है। गौरतलब है कि पटवारियों द्वारा लंबे समय से पटवारी कार्यालयों के सुचारू संचालन एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए लगातार मांग की जा रही थी।

पक्का मकान से छलकी छेरकीन की खुशी

पीएम आवास: यह सिर्फ पक्का मकान नहीं बुढ़ापे का सहारा है

रायपुर। जंगलों के बीच कच्चे मकान में बसर कर रही छेरकीन बाई को लगता था कि एक दिन वे लोग भी पक्के मकान में निवास करेंगे। घर की गरीबी और परिस्थितियों ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि पक्का आवास का सपना महज सपना ही रह गया। वक्त के साथ छेरकीन बाई अकेली ही अपनी झोपड़ी में रह गई। बच्चे भी नहीं थे। बुढ़ापे में बाल पक गए, उम्मीदें टूट गई और इन टूटे हुए उम्मीदों के बीच उन्हें बारिश के दिनों समस्याओं से जूझना पड़ता था। इस बीच प्रधनमंत्री आवास योजना में उनका नाम चयन होने के बाद जब पक्के मकान के लिए पहली किस्त मिली तो वृद्धा छेरकीन बाई ने अपने सगे संबंधियों की मदद से मकान तैयार करा लिया। अब जबकि बारिश का माहौल है, तब भी छेरकीन बाई को छत से पानी टपकने और खपरैल ठीक कराने की समस्याओं से दो चार होना नहीं पड़ता। कोरबा विकासखण्ड अंतर्गत वनांचल ग्राम केराकछार की रहने वाली

छेरकीन बाई ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास में नाम आने के बाद उन्होंने अपने घर के पास रहने वाले अन्य रिश्तेदारों के साथ ही अपना भी मकान बनवा लिया है। बारिश की वजह से अभी प्लास्टर का काम शेष है। आने वाले दिनों में प्लास्टर का काम भी पूरा हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि मकान बनकर तैयार है, और बारिश में वह इसी पक्के मकान में ही रह रही है। वृद्धा छेरकीन बाई ने बताया कि गरीबी की वजह से पक्का मकान बना पाना हमारे वश में नहीं था। घर में अकेली होने की वजह से कच्चे मकान में बारिश के दिनों में होने वाली परेशानियों से जूझना पड़ता था। वह तो पक्के मकान का उम्मीद छोड़ भी चुकी थी, लेकिन पीएम आवास में नाम आने के बाद उनकी टूटी हुई उम्मीद पूरी हो गई। उन्होंने बताया कि अपने नाती को गोद ली है और अब वे ही उनका देख-रेख करते हैं।

भिलाई स्टील प्लांट में लगी भीषण आग, उत्पादन बंद

भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) में शुक्रवार की देर रात करीब 11:40 बजे ब्लास्ट फर्नेस क्रमांक-8 में अचानक भीषण आग लग गई। हॉट एयर निकासी वॉल्व से निकलते कोयले के कणों में आग भड़क गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही बीएसपी फायर ब्रिगेड की चार दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब डेढ़ से दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग से आसपास लगे विद्युत केबल भारी मात्रा में जलकर खाक हो गए। आगजनी की वजह से ब्लास्ट फर्नेस-8 की विद्युत आपूर्ति रोक दी गई है और फिलहाल उत्पादन बंद कर दिया गया है। बीएसपी प्रबंधन ने कहा है कि मरम्मत कार्य तेजी से जारी है और स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। संभावना जताई गई है कि सेकंड शिफ्ट से उत्पादन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। घटना के समय ब्लास्ट फर्नेस-8 में रोजाना की तरह उत्पादन का कार्य चल रहा था।

छायाचित्र प्रदर्शनी और क्विज प्रतियोगिता में युवा लें रहे उत्साह से हिस्सा

लुभा रही जनसंपर्क विभाग की छायाचित्र प्रदर्शनी

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती वर्ष पर राजधानी के टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा लगायी गई छायाचित्र प्रदर्शनी राजधानीवासियों को लुभा रही है। इस प्रदर्शनी में केबीसी के तर्ज पर यहां क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। युवा इसमें उत्साह के साथ हिस्सा लें रहे हैं। छायाचित्र प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ की परंपराओं, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, छत्तीसगढ़ के पुरोधाओं का जीवन परिचय और उनका स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान तथा राज्य निर्माण की यात्रा से जुड़ी कई दुर्लभ तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। साथ ही डिजिटल स्क्रीन पर स्लाइड शो भी के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों प्रदर्शित की जा रही है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस छायाचित्र प्रदर्शनी में प्रगति पथ पर छत्तीसगढ़, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषक उन्नति योजना, महतारी वंदन योजना, विष्णु का सुशासन-संवाद से समाधान तक, सुशासन तिहार छत्तीसगढ़ अंजोर, राज्य का प्रथम आदिवासी संग्रहालय, स्वर्णिम भविष्य की राह, औद्योगिक नीति, नई शिक्षा नीति से भविष्य उज्ज्वल, वनांचल मा समृद्धि के आधार हमर हरा सोना जैसी लोककल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और छत्तीसगढ़ राज्य की उपलब्धियां को भी प्रदर्शित किया गया है। 21 अगस्त तक चलने वाली यह सात दिवसीय प्रदर्शनी प्रातः 10.30 से रात्रि 8 बजे तक आम लोगों के लिए निःशुल्क खुली रहेगी।

जे.आर. दानी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं के दल ने आज प्रदर्शनी का अवलोकन किया और क्विज में हिस्सा भी लिया। इस दौरान कु. सरिता यादव, कु. कशिश श्रीवास, कु. हेमा पटेल और कु. छाया लालवानी ने कहा कि प्रदर्शनी रोचक और ज्ञानवर्धक है। प्रदर्शनी में आगंतुकों के लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास और सामान्य ज्ञान पर आधारित क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें रायपुर के विभिन्न स्कूलों और छात्रावासों के बच्चों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर रायपुर जिले में किया जा रहा डिजिटल क्रॉप सर्वे

किसानों को अब आसानी से बीमा एवं अन्य योजनाओं का मिलेगा लाभ

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर रायपुर जिले में सभी तहसीलों में डिजिटलक्रॉप सर्वे किया जा रहा है। 15 अगस्त से शुरू हुआ यह सर्वे 30 सितम्बर तक चलेगा। डिजिटल का सर्वे का मुख्य उद्देश्य किसानों की वास्तविक फसल स्थिति का आकलन कर उन्हें राज्य एवं केंद्र शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाना है। इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे किसानों की समृद्धि और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे खेती को नई तकनीक से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर अपर कलेक्टर सुश्री नम्रता जैन ने मोहंदी, अपर कलेक्टर राठौर ने मेहरसखा में, इसी प्रकार अपर कलेक्टर श्री नवीन ठाकुर ने मंगसा, एसडीएम नंदकिशोर चौबे ने ग्राम नकटी में, एसडीएम रवि सिंह ने छाटा, एसडीएम आशुतोष देवांगन ने ग्राम अडसेना, अभिलाष पैकरा ने छतौना में डिजिटल फसल सर्वे का निरीक्षण किया। इसी प्रकार तहसीलदारों ने अपने प्रभार क्षेत्र के ग्रामों का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे फिल्ड स्तर पर सर्वेयर के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें सर्वेयर को स्वयं खेत में जाकर वहां की स्थिति और फसल का विवरण एग्रीटेक एप्प में दर्ज करना होता है। साथ में फ़ोटो अपलोड करना होता है जिसके सत्यापन बाद में पटवारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा इससे फसल का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सकेगा और जमीन की जो परिसम्मति है उनके संबंध में सही जानकारी प्राप्त होगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे से किसानों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। फसल बीमा योजना एवं क्षति आकलन पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकेगा। पात्र किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ शीघ्रता से मिल सकेगा। इस सर्वे से फसल उत्पादन का अत्याधुनिक डेटा तैयार होगा, जिससे आगामी धान खरीदी व्यवस्था एवं कृषि नीति और अधिक प्रभावी बनाई जा सकेगी। साथ ही किसानों को समय पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं आर्थिक सहयोग भी उपलब्ध हो सकेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की ओर से प्रस्तुत मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। विचार-विमर्श के उपरांत समिति ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये। बैठक में सर्वप्रथम वार्षिक कार्य मूल्यांकन (सीआर) व्यवस्था में पारदर्शिता लाने पर सहमति बनी। अब राज्य और जिला स्तर पर ऐसे पदों के लिए, जिनके स्वीकारकर्ता अधिकारी मिशन संचालक होंगे, अपील सुनवाई का अधिकार स्वास्थ्य विभाग के भारसाधक सचिव को मिलेगा। वहीं जिला और विकासखंड स्तर पर, जहां स्वीकारकर्ता अधिकारी कलेक्टर अथवा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होंगे, वहां अपील मिशन संचालक के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी। अपीलीय अधिकारी को प्रतिकूल टिप्पणी अथवा सेवा समाप्ति संबंधी आदेश को मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, मेडिकल अवकाश सुविधा के अंतर्गत दुर्घटना या गंभीर बीमारी की स्थिति में 30 दिन का सवैतनिक अवकाश देने का निर्णय लिया गया। 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि के विषय पर चर्चा करते हुए समिति ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप जुलाई 2023 की स्थिति में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को माह जुलाई 2023 की स्थिति में कार्यरत कर्मचारियों वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024 तक तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिये जाने पर समिति द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई।

10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 30 दिन का मेडिकल अवकाश

कुण्डपान में 62 करोड़ की लागत से बने विद्युत विस्तार कार्य का शुभारंभ

रायपुर। आदिम जाति विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम आज बलरामपुर जिले के विकासखंड रामचंद्रपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कुण्डपान में आयोजित कार्यक्रम में 62 करोड़ रूपए की लागत से बने विद्युत विस्तार कार्य का शुभारंभ किया। कुण्डपान में हुए विद्युत विस्तार से निश्चित ही आगामी दिनों में बिजली जैसी बुनियादी सुविधा अब बाधित नहीं होगी। इस कार्य से क्षेत्र के 1077 मंजरा टोला के कुल 11 हजार 762 परिवारों के घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। उन्होंने इस दौरान ग्राम पंचायत डिंडो में एक करोड़ 91 लाख 51 हजार रुपये की लागत से बनने वाले 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का भी शिलान्यास किया। इस छात्रावास के निर्माण से क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर मिल सकेंगे।

मंत्री श्री नेताम ने शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कुण्डपान में विद्युत विस्तार ग्रामीणों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव लाएगी। अब बच्चों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त रोशनी मिलेगी, किसानों को कृषि कार्य में सहूलियत होगी और महिलाओं को भी घरेलू कार्यों में राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा अनुरूप केंद्र एवं राज्य सरकार समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। शासन द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनसे निम्न वर्गीय एवं जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है।

राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन में शामिल हुई बगीचा की सुमन तिर्की

रायपुर। यह मेरे लिए अविस्मृत करने वाला पल था जब मुझे महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे यह पल जीवन भर याद रहेगा कि मुझे माननीय राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बात करने का अवसर भी मिला। वार्तालाप के दौरान मैने शासकीय योजनाओं के माध्यम से गांव के विकास और लोगों के जीवन में हो रहे सकारात्मक बदलाव के बारे में बताया। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने सभी का उत्साहवर्धन किया। यह कहना है प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत नगर पंचायत बगीचा की हितग्राही श्रीमती सुमन तिर्की का, जिन्हें 15 अगस्त 2025 स्वंतत्रता दिवस के पावन संध्या पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित एट होम रिसेप्शन में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ था। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट-होम स्वागत समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद, भारत के प्रधान न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला, केंद्रीय मंत्रीगण, राजनयिक, विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात व्यक्तित्व, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी, दिव्यांगजन तथा विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा देश के समस्त राज्यों से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत उपरोक्त कार्यक्रम हेतु प्रतिभागियो का नामांकन मंगाया गया था। भारत सरकार द्वारा समस्त राज्यों से प्राप्त नामांकन के विरूद्ध 09 राज्य के 10 हितग्राहियो का चयन एट होम रिसेप्शन के लिए किया गया है, छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 01 हितग्राही श्रीमती सुमन तिर्की को यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है।

उद्योग मंत्री 18 अगस्त को कोरबा में करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा

रायपुर। वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन सोमवार 18 अगस्त को जिला पंचायत कोरबा सभागृह में प्रातः 11.30 बजे नगर निगम कोरबा के विभिन्न विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं की समीक्षा बैठक लेंगे। जारी प्रोटोकॉल के मुताबिक मंत्री श्री देवांगन प्रातः 11.15 बजे चारपारा कोहड़िया से जिला पंचायत सभागृह के लिए रवाना होंगे। शाम 4.30 बजे रूमगड़ा निवासी श्री कृष्ण कुमार जी परिवार के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने के पश्चात रायपुर के लिए रवाना होंगे।

मुख्यमंत्री की पहल पर संचालित हो रहे रोजगारमूलक कई कोर्स

स्किल डेव्हलपमेंट से जशपुर की बेटियां बन रही आत्मनिर्भर

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्किल डेव्हलपमेंट के कई नवीनतम कोर्स संचालित किए जा रहे है। जशपुर के नवगुरूकुल शिक्षण संस्थान में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ने की इच्छुक युवतियों को बिजनेस एवं टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यहां आनी वाली युवतियों को हॉस्टल, भोजन एवं लैपटॉप जैसी आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियाँ भी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकें।

कुनकुरी की कुमारी नेहा खाखा ने 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद जशपुर के नवगुरूकुल शिक्षण संस्थान में प्रवेश परीक्षा पास कर फाइनेंस स्किल प्रोग्राम जॉइन किया। एक वर्ष के अध्ययन उपरांत आज वे इसी संस्थान में एसोसिएट टीचर के रूप में कार्यरत हैं और प्रतिमाह 15 हजार रुपए का वेतन प्राप्त कर रही हैं। वे कहती हैं कि नवगुरूकुल ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। यहाँ आकर मैंने एआई फीचर और गूगल शीट जैसे आधुनिक टूल्स को सीखा। आज मैं न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हूँ बल्कि अन्य छात्राओं को पढ़ाकर उन्हें भी आगे बढ़ा रही हूँ।

पत्थलगाँव की कुमारी वृंदावती यादव ने प्रोग्रामिंग स्कूल जॉइन किया। 15 माह के कोर्स उपरांत वे आज पार्ट-टाइम इंटर के रूप में कार्य कर रही हैं और प्रतिमाह 13 हजार रुपए कमा रही हैं। मुझे लगा था कि आर्थिक स्थिति के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, आज मैं पढ़ाई के साथ काम कर रही हूँ और खुद को तकनीकी रूप से सक्षम महसूस करती हूँ। बगीचा की कुमारी उषा यादव को बचपन से ही डिजाइनिंग का शौक था, परंतु पारिवारिक आर्थिक स्थिति के कारण वे ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स नहीं कर पाईं। उन्होंने निःशुल्क ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी अब मैं बिजनेस की पढ़ाई कर रही हूँ और आगे खुद का स्टार्टअप शुरू करने का सपना देख रही हूँ।

साप्ताहिक शहर सत्ता

19 अगस्त को साय कैबिनेट की बैठक कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

कृषि, उद्योग, महिला सशक्तिकरण-शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर होगी चर्चा

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट बैठक 19 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नया रायपुर मंत्रालय में होगी। इस बैठक में कृषि, उद्योग, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। वहीं, केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य स्तर पर लागू करने के संबंध में भी निर्णय लिए जाने की संभावना है। यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि सीएम साय के विदेश प्रवास से पहले मंत्रिमंडल विस्तार तय माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि सरकार अब तक कई बड़े मुद्दों पर फैसले टालती आई है, ऐसे में इस बैठक से जनता को कुछ ठोस घोषणाओं की उम्मीद है।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह बैठक अहम है क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और मंत्रिमंडल में खाली पड़े पदों को लेकर सवाल उठा रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिरकार साय कैबिनेट की इस बैठक से कौन से बड़े फैसले निकलते हैं और नए मंत्रियों के नामों पर कब मुहर लगती है।

साय केबिनेट में 21 या 18 अगस्त तक शामिल होंगे 3 नए मंत्री

शहर सत्ता/रायपुर। विष्णुदेव साय मंत्री मंडल विस्तार से जुडी बहुप्रतीक्षित नए मंत्रियों के सम्बन्ध में एक बड़ी खबर चर्चा में है। साय केबिनेट में 21 या 18 अगस्त तक 3 नए मंत्री मंडल में शामिल होंगे। CM विष्णुदेव साय 21 अगस्त को विदेश रवानगी से पूर्व अपने मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को शामिल करके ही जायेंगे। छत्तीसगढ़ में मंत्री मंडल विस्तार को केंद्रीय संगठन से भी मंजूरी मिल गई है। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी विदेश यात्रा से पहले नए मंत्रियों को शपथ दिलाकर या फिर उनके नामों की घोषणा करके ही जायेंगे। 18 अगस्त नहीं तो 21 अगस्त को छत्तीसगढ़ के नए मंत्रियों का नाम वजूद में आ जायेगा। बता दें कि CM साय 21 अगस्त को जापान और दक्षिण कोरिया रवाना होंगे। ऐसे में रवानगी से पहले उक्त दो तारीखों में से एक में नए मंत्रियों के नाम का एलान किया जायेगा। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल रामेन डेका राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। बताते हैं कि रायपुर, बिलासपुर-सरगुजा और दुर्ग संभाग से नए और पहली बार निर्वाचित विधायक शामिल होंगे।

केशकाल की कथित मुठभेड़ की जांच करेगी कांग्रेस

कोंडागांव। जिले के केशकाल थाना इलाके में हुई कथित नक्सली मुठभेड़ अब विवादों में घिर गई है. कांग्रेस ने इसे पहले ही फर्जी बता चुकी है, अब इसकी जांच के लिए कांग्रेस ने कमेटी भी बना दी है. वहीं मोहन मरकाम भी कई लोगों के साथ ग्राउंड जीरो पहुंचे जहां, ये मुठभेड़ हुई थी. पहले जानिए क्या है मामला: पुलिस के मुताबिक, केशकाल के नालाझार जंगल में 14 अगस्त की रात 10 बजे नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक ग्रामीण घायल हुआ है. घायल युवक का इलाज जिला अस्पताल में जारी है. अस्पताल में मुलाकात के दौरान घायल युवक ने कांग्रेस नेताओं को बताया कि वह अपने 3 साथियों के साथ शिकार के लिए जंगल गया था. तभी पुलिस ने उनकी गाड़ी तोड़ी और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें उसे गोली लगी. यानी ये नक्सली मुठभेड़ नहीं थी. मामले की सच्चाई जानने जिला कांग्रेस कमेटी की टीम पूर्व मंत्री मोहन मरकाम के नेतृत्व में ग्राउंड जीरो पहुंची. निरीक्षण के बाद मरकाम ने आरोप लगाया कि पुलिस "भोले-भाले ग्रामीणों को नक्सली बताकर हत्या की साजिश रच रही है." उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर मुठभेड़ के कोई सबूत नहीं मिले.

पूर्व विधायक बोले अपराधियों पर पुलिस की वर्दी का खौफ खत्म

निर्दोष आदिवासियों को मारा जा रहाः विकास उपाध्याय

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी अब अपराधपुर बन चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले कई वादे किए थे, लेकिन आज हालात यह हैं कि अपराधी न सिर्फ अपराध कर रहे हैं, बल्कि खुलेआम सोशल मीडिया फोटो भी पोस्ट कर रहे हैं। विकास ने केशकाल थाना क्षेत्र में हुई कथित नक्सली मुठभेड़ को लेकर कहा कि ऐसे मामले भाजपा सरकार के 15 साल के कार्यकाल में भी सामने आती रही हैं। बार-बार हमारे नेता सवाल उठाते रहे है कि बेगुनाह आदिवासी भाइयों को मुठभेड़ में मार दिया जाता है। उपाध्याय ने कहा कि सरकार की कार्यशैली पर यह बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्रदेश में स्टील माफिया, जमीन माफिया और नशा माफिया बेलगाम हैं। राज्य और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के बावजूद, नशे का सामान जो पहले इंटरनेशनल मार्केट में बिकता था, अब छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। इसके चलते हर छोटी-छोटी बात पर हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं। धमतरी की घटना का जिक्र करते हुए विकास उपाध्याय ने कहा कि तीन नौजवानों की हत्या करने वाले आरोपी पुलिस कस्टडी में विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अपराधियों में इतनी हिम्मत कहां से आ रही है। विकास ने कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था कमजोर हो चुकी है, पुलिस की वर्दी का खौफ अपराधियों में खत्म हो गया है।

कानून-व्यवस्था मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता: गृहमंत्री शर्मा

शहर सत्ता/रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन, मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रदेश की कानून-व्यवस्था, पुलिस भर्ती, प्रशिक्षण, भवन निर्माण और मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जैसे कई अहम मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत नशे के कारोबार के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान से हुई। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में मादक पदार्थों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि हर मामले में पूरी तरह से एंड-टू-एंड जांच हो, जिसमें तस्करी के पूरे नेटवर्क, आर्थिक लेन-देन और जुड़े लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाए, ताकि नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त किया जा सके। बैठक में ड्रग नष्टिकरण की रेंजवार रिपोर्ट और पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत हुई कार्रवाइयों की भी जानकारी ली। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, जेल डीजी श्री हिमांशु गुप्ता के अलावा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

पुलिस भर्ती को लेकर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सभी भर्तियां पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी हों। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण में अनावश्यक देरी न हो तथा तैनाती के साथ ही उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

नाकामियों से ध्यान भटकाने पर्यटन पर विदेश जा रहे मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री के विदेश प्रवास पर तंज कसते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मंत्रिमंडल में विस्तार कर नहीं पा रहे हैं, संगठन विस्तार में सिर फुटौव्वल मची है, पूर्णकालिक सीएस और डीजीपी बना नहीं पाए, विकास कार्य अवरुद्ध है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दे नहीं पा रहे, सड़के और सरकारी भवन रखरखाव के अभाव में जर्जर हो रहे हैं, शासन व्यवस्था दुरुस्त करने में यह सरकार असहाय नज़र आ रही है, इन्हीं नाकामियों को छुपाने और मुद्दों से ध्यान भटकने के लिए मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रवास पर विदेश यात्रा करने निकल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा की सरकार विगत पौने दो साल में छत्तीसगढ़ में उद्योगों के अनुकूल वातावरण बनाने में पूरी तरह नाकाम रही है। छत्तीसगढ़ स्टील उत्पादन में अग्रणी राज्य है, भाजपा की सरकार बनने के बाद से लगातार बिजली के दाम बढ़ाए गए जिसके चलते लौह उत्पादक हमारे प्रतिद्वंद्वी राज्यों उड़ीसा और झारखंड की तुलना में औद्योगिक बिजली दर डेढ़ गुना अधिक हो गया है, छत्तीसगढ़ में उत्पादन लागत बढ़ने के कारण सैकड़ो स्पंज आयरन और रोलिंग मिलें लगातार बंद हो रहे हैं

कवर्धा में स्वतंत्रता दिवस समारोह में अनदेखी

सफेद की जगह काले कबूतर उड़ाए जाने पर विवाद

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई। ग्राम पंचायत गुढ़ा के स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण के बाद शांति और सौहार्द का संदेश देने के लिए कबूतर उड़ाने की परंपरा निभाई गई, लेकिन यहां सफेद कबूतरों की जगह काले कबूतर छोड़े गए। इस घटना ने कार्यक्रम की गरिमा को धूमिल कर दिया और इसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य एवं सभापति वीरेन्द्र साहू ने कबूतर उड़ाने की रस्म निभाई। इसका वीडियो खुद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किया गया, जो तेजी से वायरल हो गया। बाद में वीडियो को एडिट कर कबूतरों को सफेद दिखाने की कोशिश भी की गई, लेकिन मूल वीडियो में काले कबूतर ही दिखाई दे रहे हैं।

लोगों ने जताई आपत्ति

स्थानीय लोगों ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर यह लापरवाही शर्मनाक है। परंपरा के अनुसार सफेद कबूतर शांति, एकता और भाईचारे का प्रतीक माने जाते हैं। काले कबूतरों को उड़ाना अशुभ और राष्ट्रीय भावना के विपरीत समझा जा रहा है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में मारपीट राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था का नमूना

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कवर्धा में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह अतिथियों के सामने सांसद संतोष पाण्डेय, एसपी कलेक्टर सभी थे कार्यक्रम में उनके सामने जिस प्रकार से मारपीट की गयी, उपद्रवी एक दूसरे को पीट रहे थे, यह बताने के लिए पर्याप्त है कि राज्य की कानून व्यवस्था कितनी बदहाल हो चुकी है। सरकार और पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर 10 दिनों के लिए जा रहे, वे जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे।

कुछ दिन पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी एक हफ्ते के अमेरिका प्रवास पर गये थे उनके वहां जाने का प्रदेश को क्या फायदा हुआ, आज तक उन्होंने प्रदेश की जनता को नहीं बताया। उपमुख्यमंत्री अरूण साव भी विदेश होकर आये है। अब मुख्यमंत्री जा रहे उम्मीद है कि उनके विदेश यात्रा का प्रदेश को कुछ फायदा मिलेगा क्योंकि इन विदेश यात्राओं पर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का लाखों रूपया खर्च होता है।

श्रीकृष्ण-जन्मोत्सव.. में सब हो गए कृष्णमय

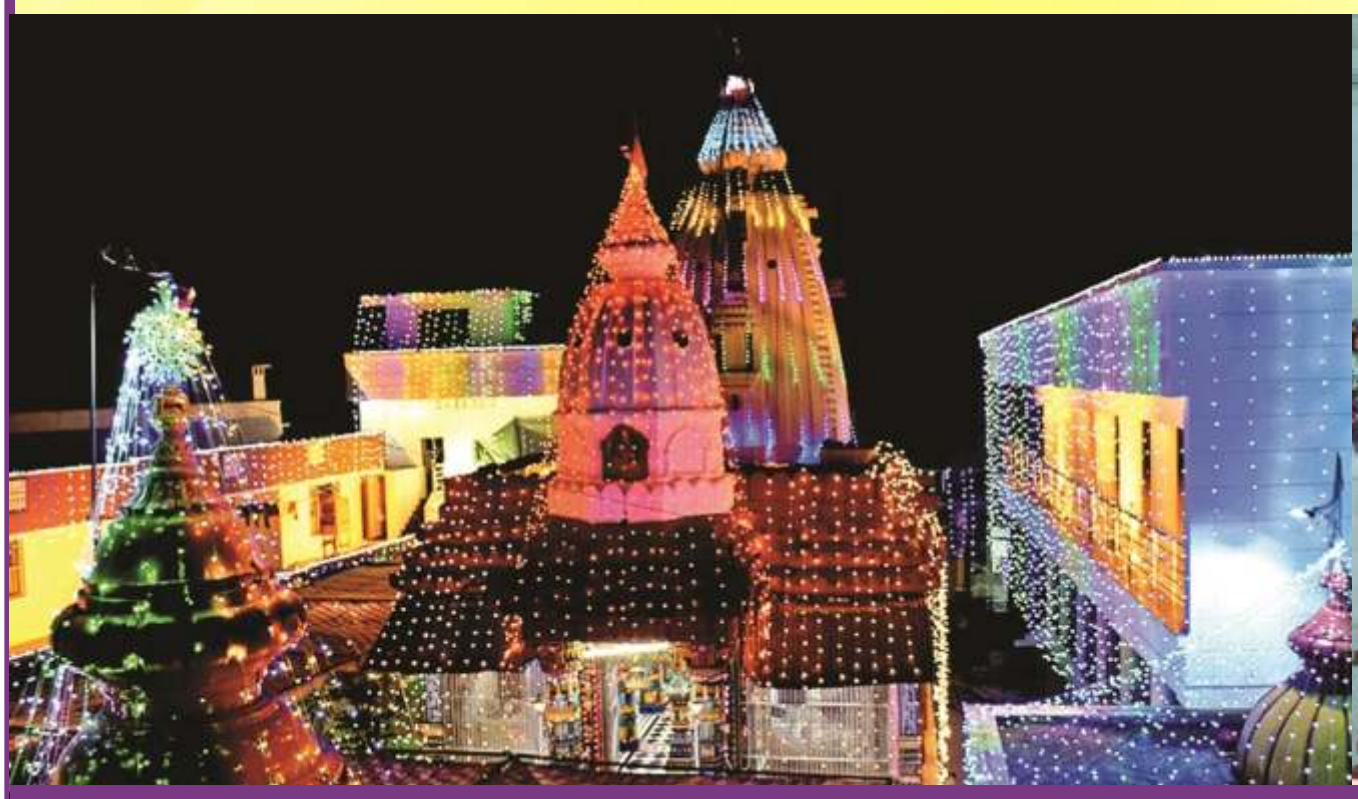

रायपुर के जैतुसाव मठ में भगवान को 1100 किलो मालपुए का भोग लगा

रायपुर के जैतुसाव मठ में भगवान को 1100 किलो मालपुए का भोग लगा, मंदिर को फूलों से सजाया गया। रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हो गया है। देशभर के साथ छत्तीसगढ़ में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। प्रदेशभर के श्रीकृष्ण मंदिरों को सजाया गया है। मंदिरों के साथ ही अलग-अलग जगहों पर भजन-कीर्तन का दौर जारी है। कई जगहों पर मटकी फोड़ के आयोजन किए गए। रायपुर के टाटीबंध स्थित इस्कॉन टेंपल में जन्माष्टमी महोत्सव चल रहा है। जैतूसाव मठ में भगवान को भोग लगाने के लिए 1100 किलो मालपुआ तैयार किया गया है। मठ में भजन, जन्म आरती कर राजभोग ठाकुरजी को लगाया गया। इसके अलावा सरगुजा, बिलासपुर और रायगढ़ में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। सरगुजा में भक्त हरिनाम कीर्तन की धुन पर झूमते हुए "हरे कृष्ण-हरे राम" के महामंत्र में डूबे हुए हैं। अलग-अलग शहरों में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

इस्कॉन मंदिर में उमड़े श्रद्धालु

शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते दिख रहे हैं. ऐसे में इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर नजारा और ज्यादा ही भक्तिमय हो जाता है. रायपुर के टाटीबंध चौक के पास स्थित इस्कॉन मंदिर देश के 150 मंदिरों में से एक है. आज आपको बताएंगे इस मंदिर की खासियत और जन्माष्टमी को लेकर कैसी है यहां तैयारी. वृंदावन की तर्ज पर भव्य आयोजन: कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिर में वृंदावन की तर्ज पर भजन कीर्तन का आयोजन सुबह से हो रहा है, जो देर रात तक चला।

अठखेलियों से गुलजार हुआ सीएम हाउस

सीएम साय ने नन्हें बाल-गोपालों संग मनाई जन्माष्टमी

रायपुर। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास और पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। बच्चों ने राधा और कृष्ण का रूप धरकर अपनी अठखेलियों और मनमोहक वेशभूषा से कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री निवास में इस बार रायपुर के बैरन बाजार स्थित आंगनबाड़ी के नन्हें-मुन्ने बच्चों के साथ सीएम साय ने जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। पूरे निवास परिसर को फूलों, रंगीन रोशनियों और सजावट से सुसज्जित किया गया, जिससे वातावरण भक्ति और उल्लास से भर गया। कार्यक्रम में छोटे-छोटे बच्चों ने कृष्ण-लीला की झांकियां और प्रसंग प्रस्तुत किए। उनकी मासूमियत और भावपूर्ण अभिनय ने उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री निवास बच्चों की हंसी और उल्लास से गुलजार रहा।

सीएम साय ने बच्चों के साथ की पूजा

मुख्यमंत्री साय ने बच्चों के साथ भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और निरंतर तरक्की की कामना की। उन्होंने कहा कि, भगवान श्रीकृष्ण की लीला हमें धर्म, नीति और कर्तव्य पालन की प्रेरणा देती है। छत्तीसगढ़ की जनता की मेहनत और आस्था से प्रदेश निरंतर प्रगति कर रहा है। हमारा संकल्प है कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरणा लेकर छत्तीसगढ़ को न्याय, सद्भाव और विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।

सीएम साय ने बच्चों को चाकलेट का वितरण किया

सीएम साय ने स्नेहपूर्वक सभी बच्चों को अपने हाथों से चाकलेट, शिक्षण सामग्री और प्रसाद का वितरण किया। कहा कि, ऐसे सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन न केवल हमारी परंपराओं को जीवित रखते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ते हैं। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

साप्ताहिक शहरसत्ता

लाल किले की प्राचीर से रायपुर पुलिस मैदान तक लहराया तिरंगा

दिवाली तक जीएसटी की दरें हो जाएंगी कमः पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस बार दिवाली में लोगों को डबल दिवाली का गिफ्ट मिलेगा. प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 8 साल में हमने जीएसटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म किया. पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया. पीएम मोदी ने कहा, ' हमने टैक्स की व्यवस्था सरल की. पिछले आठ वर्षों में हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है और देश भर में कर का बोझ कम किया है. हम अगली पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म ला रहे हैं.'

पीएम मोदी ने कहा, ' 8 साल बाद समय की मांग है कि उसका रिव्यू किया जाए जिसके बाद हमने एक हाइ पावर रिव्यू कमेटी बनाई और रिव्यू शुरू किया. राज्यों से भी विचार-विमर्श किया. हम नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं. ये दीवाली के लिए अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे. सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे. हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्योगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी. उससे अर्थव्यवस्था को भी एक नया बल मिलने वाला है.' पीएम मोदी के एलान के बीच वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल को एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें स्ट्रक्चरल रिफऑर्म, टैक्स रेट को कम करने के साथ जीएसटी को और आसान बनाने की बात कही गई है। लाल किला की प्रचीर से देश के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जीएसटी को एक बड़े सुधार का रूप करार दिया। प्रधानमंत्री के अनुसार, साल 2017 में लागू हुई जीएसटी के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया रूप मिला है। इस बीच पीएम मोदी ने इसमें नेक्स्ट जेनेरेशन जीएसटी का जिक्र किया है, जिसके संबंध में प्रस्ताव भेज दिया गया है। आइए आपको बताते हैं इससे क्या-क्या बदलने वाला है?

मिलकर बनाएंगे विकसित छत्तीसगढ़ - सीएम साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउण्ड में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का दिन है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ते हुए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर हमें स्वतंत्रता का उजाला सौंपा।

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और सेना के वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि हम छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 गौरवशाली वर्षों की विकास यात्रा को "छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव" के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने यह भी घोषणा कि रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जल्द ही लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस अवसर पर हम विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लें। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय अटल जी के सुशासन का दृढ़ संकल्प हमें शक्ति देता है। हम निश्चित ही जन-जन की सहभागिता से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लक्ष्य को साकार करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन "रामकाजु कीन्हें बिनु मोहि कहां बिश्राम" हमारा आदर्श वाक्य है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत हमारे पथप्रदर्शक हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी को जन-आंदोलन का रूप दिया है। आत्मनिर्भर भारत 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दुर्ग में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली

रायपुर। दुर्ग जिले की गौरवशाली परम्परा के अनुरूप 79वें स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास वातावरण में पूरी गरिमा के साथ समारोहपूर्वक मनाया गया। मुख्य समारोह का

आयोजन प्रथम बटालियन ग्राउंड भिलाई में किया गया, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का प्रदेश की जनता के नाम दिये संदेश का वाचन किया। उपमुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया तथा समारोह में सम्मिलित सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। समारोह में परेड द्वारा हर्ष फायर किया गया और राष्ट्रपति की जय-जयकार की गई। उत्साह व उमंग के प्रतीक रंग-बिरंगे गुब्बारे आकाश में उड़ाये गये। मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी ली। स्कूली छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति गीत और पारंपरिक गीतों पर सामूहिक सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुतियों से सभी दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि ने समारोह में उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीद जवानों के परिजनों को शॉल व श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की अत्यंत मनमोहक और आकर्षक प्रस्तुति दी गई। मुख्य अतिथि ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालय के प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार वितरण किया।

राज्यपाल रमन डेका ने राज भवन में किया ध्वजारोहण

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुबह राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं परेड की सलामी ली। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी भी उपस्थित थी। राज्यपाल ने राजभवन सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने राजभवन के कर्मचारियों के परिजनों एवं बच्चों से आत्मीयता से मुलाकात की और बच्चों को टॉफी-मिठाई वितरित की। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर प्रसन्ना, विधिक सलाहकार श्री भीष्म प्रसाद पाण्डेय, उप सचिव श्रीमती निधि साहू सहित राजभवन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

स्वतंत्रता दिवस पर उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने किया ध्वजारोहण

रायपुर। आजादी का 79 वां पर्व जिले में गरिमामय माहौल में उत्साहपूर्वक मनाया गया। पुलिस ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान की धुन पर सलामी ली। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने शांति के प्रतीक सफेद कबूतर उड़ाए और हर्षोल्लास और उमंग के प्रतीक तिरंगे गुब्बारे आकाश में छोड़े। इस अवसर पर 13 प्लाटूनों ने भव्य एवं आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया। श्री साव ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन कर नक्सल हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिवारों को सम्मानित किया। शासकीय कार्यों एवं दायित्वों के उत्कृष्ट निर्वहन के लिए विभिन्न विभागों में कार्यरत 118 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रावीण्य सूची में स्थान हासिल करने वाले 10 वीं एवं 12 वीं की बच्चों एवं उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूल के प्राचार्यों को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। परेड में पहला स्थान सीनियर वर्ग में जिला महिला पुलिस बल, दूसरा स्थान नगर सेना पुरूष को मिला। जूनियर वर्ग में पहला स्थान एनसीसी सीनियर डिवीजन गर्ल्स में बिलासा गर्ल्स कॉलेज को मिला।

स्वतंत्रता दिवस पर रेलवे सुरक्षा बल, बैंड डिस्प्ले का आयोजन

रायपुर। 15 अगस्त-2025 की संध्या पर रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के बैंड टीम द्वारा समय 17-30 बजे से 18-30 बजे तक बैंड डिस्प्ले किया किया, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल के बैंड मास्टर श्री टी.आर. यादव के साथ अन्य बैंड सदस्य भाग लिए, यह आयोजन ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन बिलासपुर VIP गेट नं.-2 के सामने किया गया। इस बैंड डिस्प्ले में कई अलग-अलग देश भक्ति धुनों को बजाया गया जिनमे मुख्य रूप से - दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन ऐ वतन हमको तेरी कसम, कदम कदम बढ़ाये जा, ऐ मेरे वतन के लोगो, आओ बच्चों तुम्हें दिखाये झांकी हिंदुस्तान की, ये देश है वीर जवानों का, सारे जहां से अच्छा और राष्ट्रगान जैसे धुनों को शामिल किया गया है।

रायपुर मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज

रायपुर। पूरे राष्ट्र के साथ 79वां स्वतंत्रता दिवस, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर मंडल के विभिन्न स्थानों पर स्थित कार्यालयों में पारंपरिक रूप से एवं हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया । मंडल का मुख्य कार्यक्रम रायपुर रेल मंडल कार्यालय के प्रांगण में आयोजित गया । इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंडल रेल प्रबंधक श्री दयानंद विशिष्ट अतिथि अध्यक्षा सेक्रो श्रीमती शिखा सिंह की गरिमामयी उपस्थिति मे मनाया गया । इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री दयानंद ने वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, श्री रमण कुमार की अगुवाई में परेड़ की सलामी ली । वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री राहुल गर्ग द्वारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम तैयार किया गया । अतिथियों के स्वागत से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तथा मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक द्वारा 9.00 बजे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान की सुमधुर धुन के साथ फहराया गया। इस अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल, सिविल डिफेंस, स्काउट गाइड के सदस्यों द्वारा मार्चपास्ट प्रस्तुत किया गया तथा मंडल रेल प्रबंधक द्वारा रेल परिवार को संबोधित किया गया । स्वतंत्रता सेनानियो को स्मरण करते हुए सभी कर्मचारियों, यात्रियों, संगठनों, सेक्रो को मंडल रेल प्रबंधक ने बधाई दी उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह ऐतिहासिक एवं गौरवशाली दिन है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन (सेक्रो) ने मनाया स्वतंत्रता दिवस

रायपुर। 79वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन (सेक्रो) रायपुर मंडल के द्वारा टिनी टॉट स्कूल –I, टिनी टॉट स्कूल –II, WRS कॉलोनी, रायपुर में ध्वजारोहण किया गया एवं शिक्षिकाओं /स्कूल के बच्चो द्वारा देश भक्ति गीत प्रस्तुत किये । साथ ही टिनी टॉट स्कूल –I, टिनी टॉट स्कूल –II, WRS कॉलोनी, रायपुर और आकांक्षा अभिलाषा स्कूल में फ़ूड पैकेट्स का वितरण किया गया। साथ ही सेक्रो संगठन रायपुर मंडल के द्वारा रायपुर मंडल रेलवे चिकित्सालय एवं बी.एम.वाय रेलवे चिकित्सालय में मरीजों को गिफ्ट एवं फ़ूड पैकेट का वितरण किया गया।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.), मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)।